CALLING ATTENTION TO THE MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Plight of stranded workers from India in Uraq and Government's response thereto

SHRIMATI AMBIKA SONI (Punjab): Mr. Deputy Chairman, Sir, I beg to call the attention of the hon. Minister of External Affairs to the plight of stranded workers from Iraq and Government's response thereto. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Minister to make a statement. ...(*Interruptions*)... Please don't do this. This is an important subject. ...(*Interruptions*)... Please sit down. ...(*Interruptions*)... Why do you do this? ...(*Interruptions*)... Why do you do this? ...(*Interruptions*)... You lay your statement on the Table. ...(*Interruptions*)...

विदेश मंत्री तथा प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): माननीय उपसभापति महोदय ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Either you lay it on the Table or you read it. ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: महोदय, मैं इस विषय पर बोलना चाहती हूं ...(**व्यवधान**)... यह गंभीर विषय है, मैं इस पर बोलना चाहती हूं ...(**व्यवधान**)... सदन मुझसे जानना चाहता है, सदन मुझसे पूछे, सांसद मुझसे पूछें ...(**व्यवधान**)... आप कहें तो मैं इसको lay कर दूं ? ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आप कहें तो मैं इसको lay कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)... आप lay कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)... lay कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: माननीय उपसभापति जी, मैं "इराक में फंसे असहाय भारतीय कामगारों की दुर्दशा और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया" के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस सदन में उत्तर देना चाहूंगी ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: मंत्री महोदया, प्लीज lay कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, मैं यह वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

*"प्रथमतः मैं इस सम्मानीय सदन में पुनः कहना चाहूंगी कि सरकार इराक में हाल ही के घटनाक्रमों तथा इराक में फंसे भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा एवं संरक्षा के संसद के माननीय सदस्यों की चिंताओं से सहमत है। लोक सभा में इस प्रकार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में मैंने इराक में फंसे भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा एवं उनकी सुरक्षित वापसी के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों का ज़िक्र करते हुए 24 जुलाई को एक वक्तव्य दिया था।

भारत सरकार इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शाम (आईएसआईएस) द्वारा अप्रत्याशित हमलों के परिणामस्वरूप इराक में जारी संघर्ष तथा बिगडती सुरक्षा स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित है। आईएसआईएस ने जिस गति से 8 जून को अपने हमले शुरू किए तथा उत्तरी एवं मध्य इराक के

*Laid on the Table.

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

कई नगरों पर कब्जा किया, उससे हर कोई हतप्रभ है। तब से इराक में सुरक्षा की स्थिति गंभीर तथा अस्थिर बनी हुई है।

इस संघर्ष की शुरूआत में इराक में भारतीयों की संख्या लगभग 22,000 थी। इनमें से बगदाद में 500, नजफ में 2,300, करबला में 1,000, बसरा में 3,000, कुर्दिस्तान में 15,000 तथा अन्य शहरों में 200 भारतीय शामिल हैं। इन अप्रत्याशित हमलों के बाद संघर्ष के क्षेत्रों में कुछ भारतीय फंस गए थे।

तिकरित शहर के एक स्थानीय अस्पताल में कार्यरत 46 नर्सों का समूह भी संघर्ष के कारण फंस गया था। उन्हें एक अज्ञात समूह द्वारा 3 जुलाई को मौसूल लाया गया था। उन्हें 4 जुलाई को रिहा कर दिया गया था तथा उसी दिन उन्हें भारत वापस लाने के लिए एयर इंडिया के एक विशेष विमान की व्यवस्था की गई थी। वे विशेष विमान द्वारा 5 जुलाई की सुबह सुरक्षित कोच्चि पहुंच गई थी, जिनके साथ 134 अन्य भारतीय कामगारों को वापस लाया गया था, जिसमें हैदराबाद में 80 तथा दिल्ली लाए गए 54 व्यक्ति शामिल हैं।

मौसुल में एक विनिर्माण कंपनी में कार्यरत लगभग 41 भारतीय राष्ट्रिकों के एक अन्य समूह को एक अन्य अज्ञात गुट ने बंदी बना लिया था। सरकार उन्हें रिहा करवाने का भरसक प्रयास कर रही है तथा सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

भारत सरकार इराक में सुरक्षा स्थिति पर नियमित रूप से पैनी नजर रखे हुए है। इराक में इस संकट की शुरूआत से ही हमने 15 जून, 24 जून तथा 28 जून को हमारे राष्ट्रिकों को नियमित रूप से यात्रा परामर्शियां जारी की हैं। भारतीय राष्ट्रिकों को अगली अधिसूचना जारी होने तक इराक की किसी प्रकार की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा ईसीआर की श्रेणी के यात्रियों द्वारा उत्प्रवासन कर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 19 जून, 2014 से प्रभावी है।

हमने इराक में हमारी राष्ट्रिकों को पुनः सलाह दी है कि वे वाणिज्यिक माध्यमों से देश छोड़ दें, यदि ऐसा करना सुरक्षित है। वर्तमान सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले हमारे राष्ट्रिकों को यह सलाह दी गई है कि वे यथासंभव घरों के भीतर ही रहें तथा उत्पन्न सुरक्षा को यह सलाह दी गई है किवे यथासंभव घरों के भीतर ही रहें तथा उत्पन्न सुरक्षा स्थिति से संबधित उद्यतन सूचना तथा आवश्यक मार्गदर्शन के लिए बगदाद स्थित हमारे दूतावास के संपर्क में रहें। जिन भारतीय राष्ट्रिकों के पास यात्रा दस्तावेज़ नहीं हैं अथवा जिन्हें एयर टिकट जैसी अन्य कोंसुली सेवाओं तथा आप्रवासन अनापत्ति के लिए सहायता की आवश्यकता है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे बगदाद स्थिति हमारे दूतावास से सहायता प्राप्त करें।

15 जून से बगदाद स्थित हमारे दूतावास तथा विदेश मंत्रालय ने विशेष नियंत्रण कक्षों में 24 घंटों की हेल्पलाइनें स्थापित की हैं ताकि इराक में हमारे राष्ट्रिकों तथा भारत में संबंधित परिवार के सदस्यों की सहायता की जा सके। इन हेल्पलाइनों के बारे में मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया है।

हमने बसरा, नजफ तथा करबला में विशेष शिविर कार्यालय भी स्थापति किए हैं तथा अतिरिक्त 25 स्टाफ सदस्य भेजकर बगदाद में अपने मिशन को सशक्त किया है। ये क्षेत्र कार्यालय भारतीय राष्ट्रिकों तथा जिन कंपनियों में वे काम करते हैं, उनसे सम्पर्क कर रहें तथा उन्हें एयर टिकट प्रदान करके तथा साथ ही आप्रवासन व प्रस्थान सहायता करके हमारे राष्ट्रिकों को इराक छोड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम लोगों ने अपने पूर्व राजपूत को इराक भेजा है, जिससे हमारे राष्ट्रिकों की सहायता हेतु दूतावास द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ बनाया जा सके और

उनका समन्यवन किया जा सके। इराक में हमारे राष्ट्रिकों को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष का उपयोग किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रिकों की वापसी से संबंधित अंतर मंत्रालयी स्थाई समूह ने स्थिति की मांग के अनुसार इराक से हमारे राष्ट्रिकों को सुरक्षित तथा शीघ्र वापस लाने के लिए ठोस आपातकालीन योजनाएं तैयार की हैं। हालाकि हमने किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए स्वंय को तैयार कर लिया है, फिर भी हम यात्रा दस्तावेजों तथा एयर टिकटों सहित हर अपेक्षित सहायता प्रदान करके हमारे राष्ट्रिकों को वापस लाने के लिए उन्हें इराक में अपेक्षाकृत सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने की सुविधा प्रदान करने में लगे हुए हैं।

2 अगस्त की स्थिति के अनुसार 4,900 से अधिक भारतीय राष्ट्रिकों को भारत की वापस यात्रा के लिए सहायता प्रदान की गई है, जिसमें शिविर कार्यालय की स्थापना के बाद से ही 3,900 से अधिक राष्ट्रिकों के लिए एयर टिकटें शामिल हैं।

भारतीय राष्ट्रिकों, विशेष रूप से मौसुल में बंदी बनाए गए 41 भारतीय राष्ट्रिकों की सुरक्षा तथा संरक्षा हमारे लिए अत्यधिक चिंता तथा तत्काल कार्रवाई का मामला है। हम उनकी सुरक्षित वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

मैं इस सम्मानित सदन को आश्वस्त करती हूं कि हमारी सरकार का यह गंभीर प्रयास रहेगा कि इस समय इराक में प्रत्येक भारतीय नागरिक की सहायता की जाए और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए।''

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House is adjourned to meet at 2.00 p.m.

The House then adjourned at thirty minutes past twelve of the clock.

The House re-assembled at two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

विपक्ष के नेता (श्री गुलाम नबी आजाद): माननीय डिप्टी चेयरमैन, बहुत अरसे से विपक्ष के सभी साथियों ने और हमारी तरफ से श्रीमती अम्बिका सोनी जी ने कॉलिंग अटेंशन के लिए नोटिस दिया था, जिसे विपक्ष के तकरीबन सभी साथियों ने सपोर्ट किया था। महोदय, यह सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के बीच का मुद्दा नहीं है। यह भारत के उन सैकड़ों लोगों का मुद्दा है जो इराक और लीबिया में फंसे हुए हैं ...(**व्यवधान**)...

† **قائد حزب اختلاف (جناب غلام نبی آزاد)** : مائنے ڈپٹی چیئرمین صاحب سر، بہت عرصے سے وپکش کے سبھی ساتھیوں نے اور ہماری طرف سے شریمتی امبیکا سونی جی نے کالنگ اٹینشن کے لئے نوٹس دیا تھا، جسے وپکش کے تقریبا سبھی ساتھیوں نے سپورٹ کیا تھا۔ مہودے، یہ ستا دھاری پارٹی اور وپکش کے بیچ کا مدّعا نہیں ہے۔ یہ بھارت کے ان سیکڑوں لوگوں کا مدّعا ہے جو عراق اور لیبیا میں پھنسے ہوئے ہیں ۔۔(مداخلت)۔۔

†Transliteration in Urdu Script.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT; THE MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION; AND THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): The Minister is in the other House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am aware of that.

श्री गुलाम नबी आजाद: इससे पहले हमारी केरल की बहुत सारी नर्सेज़ इराक में फंसी हुई थीं। मैं फॉरेन मिनिस्टर को, इराक में जो हमारा कमीशन है, उसे और केरल की सरकार को, क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने भी उसमें बहुत काम किया, बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से ऐसा हो पाया। कांग्रेस, बीजेपी और जितनी अपोजिशन की पार्टीज़ है, उन सभी ने इकट्ठे मिलकर इसमें काम किया, जो-जो भी सहयोग किसी का हो सकता था, डिप्लोमैटिक चैनल से या नॉन-डिप्लोमैटिक चैनल से, सभी ने सहयोग दिया और उसका परिणाम यह हुआ कि हमारी केरल की सैकड़ों नर्सेज़ और दूसरे लोग वहां से वापस आ गए। इसी तरह से लीबिया में बहुत सारे लोग फंसे थे, जिस पर बड़ी चर्चा हुई कि वैस्ट एशिया में हजारों और लाखों, मिलियंस एंड मिलियंस हिन्दुस्तानी रहते हैं, उनका रोज़गार उस पर निर्भर है और एम्प्लॉयमेंट के साथ-साथ हमारे देश की इकोनॉमी को भी उससे बूस्ट मिलता है। लीबिया से भी अब एक ग्रुप वापस आया है, हम उनका स्वागत करते हैं और जो भी प्रयास हुए हैं उसके लिए आपको बधाई देते है। आज कई दिनों के बाद कॉलिंग अटेंशन मंजूर हो गया था कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद उस पर चर्चा होगी। उसमें तकरीबन सभी पक्षों के लीडर्स ने और सरकार ने भी अपनी सहमति जाहिर की थी, लेकिन प्रश्नकाल के बाद यहां बड़ा शोर-शराबा और हल्ला-गुल्ला हुआ, जिसके चलते अम्बिका सोनी जी ने, जो कॉलिंग अटेंशन आपने मंजूर किया था, उस पर चर्चा करनी चाही । उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज जी उस पर स्टेटमेंट देना चाहती थीं, लेकिन शोरगुल के चलते वह स्टेटमेंट किसी से सुना नहीं जा सका। उसके बाद दो बजे तक सदन स्थगित किया गया। हमने, सभी पार्टियों के लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की थी, जिस वक्त आपने साढ़े बारह बजे हाउस को दो बजे तक स्थगित किया, हम सबने कहा कि बड़े अरसे के बाद यह मामला आया है, यह किसी पार्टी या पक्ष का मामला नहीं हैं, भारतीय लोगों का मामला है, इसलिए इसे दो बजे लेना चाहिए। हमारा आप सबसे और सरकार से यह अनुरोध है कि विपक्ष की तरफ से जितने भी हमारे लोग इस पर बोलना चाहते हैं, उन्हें मौका दें। सरकार की तरफ से, उस पार्टी से भी अगर कोई बोलना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनका स्वागत है। यह भारतीयों का मामला है, इसलिए हमारा आपसे अनुराध है कि इस कॉलिंग अटेंशन को अब लिया जाए, नॉर्मली नहीं लिया जाता है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको दिमाग में रखते हुए आप इसकी अनुमति दें।

† **جناب غلام نبی آزاد :** اس سے پہلے ہماری کیرل کی بہت ساری نرسیز عراق میں پھنسی ہوئی تھیں۔ میں فارن منسٹر کو، عراق میں جو ہمارا کمیشن ہے، اسے اور کیرل کی سرکار کو، کیوں کہ مکھیہ منتری جی نے بھی اس میں بہت کام کیا، بدھائی دیتا ہوں کہ ان کے پریاس سے ایسا ہو پایا۔ کانگریس،

† Transliteration in Urdu Script.

بی۔جے۔پی۔ اور جتنی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، ان سبھی نے اکٹھے مل کر اس میں کام کیا، جو۔جو بھی سہیوگ کسی کا ہو سکتا تھا، ڈپلومیٹک چینل سے یا نان۔ڈپلومیٹک چینل سے، سبھی نے سہیوگ دیا اور اس کا پرینام یہ ہوا کہ ہماری کیرل کی سیکڑوں نرسیز اور دوسرے لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ اسی طرح سے لیبیا میں بہت سارے لوگ پھنسے تھے، جس پر بڑی چرچا ہوئی کہ ویسٹ ایشیا میں ہزاروں اور لاکھوں، ملینس اینڈ ملینس ہندوستانی رہتے ہیں، ان کا روزگار اس پر نربھر ہے اور ایمپلائمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش کی اکانومی کو بھی اس سے بوسٹ ملتا ہے۔ لیبیا سے بھی اب ایک گروپ واپس آیا ہے، ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور جو بھی پریاس ہوئے ہیں اس کے لئے آپ کو بدھائی دیتے ہیں۔ آج کئی دنوں کے بعد کالنگ اٹینشن منظور ہو گیا تھا کہ پرشن کال کے فورا بعد اس پر چرچا ہوگی۔ اس میں تقریبا سبھی پکشوں نے لیڈرس نے اور سرکار نے بھی اپنی سہمتی ظاہر کی تھی، لیکن پرشن کال کے بعد یہاں بڑا شور شرابہ اور ہلّہ گلّہ ہوا، جس کے چلتے امبیکا سونی جی سے، جو کالنگ اٹینشن آپ نے منظور کیا تھا، اس پر چرچا کرنی چاہی۔ اس کے بعد فارن منسٹر شریمتی سشما سوراج جی اس پر اسٹیٹمینٹ دینا چاہتی تھیں، لیکن شوروغل کے چلتے وہ اسٹیٹمینٹ کسی سے سنا نہیں جا سکا۔ اس کے بعد دو بجے تک سدن استھگت کیا گیا۔ ہم نے، سبھی پارٹیوں کے لوگوں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی، جس وقت آپ نے ساڑھے بارہ بجے باؤس کو دو بجے تک استھگت کیا، ہم سب نے کہا کہ بڑے عرصے کے بعد یہ معاملہ آیا ہے، یہ کسی پارٹی یا پکش کا معاملہ نہیں ہے، بھارتی لوگوں کا معاملہ ہے، اس لئے اسے دو بجے لینا چاہئے۔ ہمارا آپ سب سے اور سرکار سے یہ انورودھ ہے کہ وپکش کی طرف سے جتنے بھی سارے لوگ اس پر بولنا چاہتے ہیں، انہیں موقع دیں۔ سرکار کی طرف سے، اس پارٹی سے بھی اگر کوئی بولنا چاہے تو ہمیں کوئی آپتّی نہیں ہے، ان کا سواگت ہے۔ یہ بھارتیوں کامعاملہ ہے، اس لئے ہمارا آپ سے انورودھ ہے کہ اس کالنگ اٹینشن کواب لیا جائے، نارملی نہیں لیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو امپورٹینس ہے، اس کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ اس کی انومتی دیں۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rajeeve, I will allow you. Now the hon. Leader of the Opposition has raised a point. But, as the House is aware, the Calling Attention Motion is to be taken up at 12 o' clock and disposed of by 1.00 p.m. That is the practice and that is the way it is done. Now the hon. LOP, because of the importance of the subject, which, I hope, everybody will agree to, has made a request that the Calling Attention Motion, which we could not complete in the morning, should be continued now. For that, I heard the LoP. I want the view of the House and I want one or two people and the Government also to react. Then we will take the sense of the House and proceed.

SHRI P. RAJEEVE: Sir,...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, what is it, Shri Rajeeve?

SHRI P. RAJEEVE: I share the views expressed by hon. LoP. It is a very important subject and we have another precedent. The Minister made a statement on my Calling Attention three years back and due to disruptions, the House adjourned. Thereafter, the then Chair allowed to discuss the Calling Attention after 2 o' clock. Then we had the precedent. I then request the Government, through the Chair, Sir, to take this Calling Attention now itself and give an opportunity to seek clarifications.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Shri Tyagi. Do you agree with this?

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) : उपसभापति महोदय, मैं इनसे भी, नेता प्रतिपक्ष से भी, आपसे भी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर से भी agree करता हूं। एक महीने से सदन में यह सवाल आया था।

SHRI D. P. TRIPATHI: Sir, I also associate with him.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, I also associate with Shri K. C. Tyagi.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay.

DR. V. MAITREYAN: Then it becomes a precedent in future also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No.

DR. V. MAITREYAN: Then you should allow urgent matters. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would like to caution...(*Interruptions*)...

DR. V. MAITREYAN (Tamil Nadu): Sir, a similar stand should be taken up for other topics also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. V. Maitreyan....(*Interruptions*)...

DR. V. MAITREYAN: Sir, an issue is important for some people and the same issue may not be important for some others. Then I demand a discussion on Lankan fishermen. The same issue...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Maitreyan, listen to me. You please listen to me. I have said that such a suggestion has come from hon. LoP. I said that I will take it up only if there is a consensus in the House.

DR. V. MAITREYAN: I am not objecting to it at all. I only urge you ...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not to be a precedent. This is not to be quoted as a precedent. Yes, hon. Minister.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Hon. Deputy Chairman, Sir, I heard the hon. Leader of the Opposition. The issue that was raised through a Calling Attention Motion was very important. Keeping that in mind, the Government wanted to respond. But, unfortunately, for a variety of reasons we could not get an occasion to take up that issue. Finally, it was taken up today. Sir, the Minister was there and she was willing to respond to that, but, unfortunately, that could not happen. I do not want to get into that and make it a controversial debate. The Government's view is, in an extraordinary situation, particularly, concerning people of Indian origin being held outside, efforts that are being made from the Government and other agencies are very much needed and that we have a proper discussion and a response from the Government on this issue. But the only thing is, as I said in the beginning, this is an extraordinary situation. We should not make it a precedent. Otherwise, every time something comes,...

DR. V. MAITREYAN: Extraordinary situation demands extraordinary treatment. There can be many extraordinary situations. If that is the case we will have tomorrow at 12 o' clock....

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: That is your view. I am talking about the Government's view.

DR. V. MAITREYAN: Mr. Deputy Chairman, if this is a ruling, then, I want to protest.

SHRI P. RAJEEVE: If you go through 'Rajya Sabha at Work', you can see...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, please sit down.

DR. V. MAITREYAN: I urge the Chair to say that this should not be a precedent.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: The Government is accepting this, not to treat this as a precedent for future.

DR. V. MAITREYAN: We will urge....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Matreyan, I will meet your point.

DR. V. MAITREYAN: Sir, it is because there will be many occasions which will be of utmost importance to us. It may not be important to them. We are also the Members of this House and we have earned our place here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Maitreyan, you please listen. The House is supreme. I have not taken a decision myself. After the hon. LoP has raised,....

DR. V. MAITREYAN: No, this should not be a precedent.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have left it to the House.

DR. V. MAITREYAN: I ask the LoP whether he will support us. On similar occasions of an extraordinary nature, will the LoP support us?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Maitreyan, nobody can give such a guarantee. It should be decided then and there.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): If such a situation arises, why not?

DR. V. MAITREYAN: That is what I am saying, don't say that it will not be a precedent.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What I said is, you know that the House is supreme. I leave it to the House. Now, there is a consensus in the House that this should be taken up. Nobody can take away the consensus of the House. Can I do that? But I said, my permission is, it is not to be taken as a precedent. The House can always decide. The House is supreme. I am a servant to the House. But, my permission should not be quoted as precedent. That is what I said.

Now, the hon. Minister has already made a statement. I had requested her to lay it on the Table. She had done that. I hope the statement is circulated. There is no need for another statement. It is time for seeking clarifications. So, I am calling Shrimati Ambika Soni. But, before that we should decide how much time can be allotted for this discussion.

SOME HON. MEMBERS: Sir, one hour.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. One hour is allotted. It means, Shrimati Ambika Soni*ji* will be given five minutes and others will confine to three minutes each.

SHRI BAISHNAB PARIDA: Sir, three minutes is too little. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. Only three minutes. Please, sit down. Your name is not there. Why more time? Your name is not there in the list of speakers.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Thank you Mr. Deputy Chairman, Sir, for giving us the opportunity of discussing this very important issue of citizens of Indian origin being held captive in a friendly country. Despite great efforts made by the hon. Foreign Minister herself personally, by her Ministry and the Embassy in Iraq, we are still stuck at 40 people whose whereabouts no one has been able to say a single word.

Sir, I have with me here a reply given to a Starred Question in this House. I have had the opportunity of reading the hon. Minister's reply in the Lok Sabha. I have also gone through the statement made by the hon. Minister to this Calling Attention. Except for the fact that 4,000 Indians have been repatriated -- now, it is 4,900 -- there is not a word which is different in any of the three replies. This really makes one wonder where the 'forward movement' is. I think, I have no hesitation in admitting that, maybe, Sushma Swarajji knows better than most other people would about the condition of our people there. She has also met family members a couple of times. What is the condition of wives, mothers, children and other family members of these 40 young people mostly from Punjab? There are one or two from other States also. Their family members are going with photographs from pillar to post to all of us -- political representatives -- pleading for help. What help they want, they don't know. All they want is their children back. I spoke to a mother yesterday in Chandigarh. She told me that the last contact she had with her son was on the 17th July, 2014. I have the name and Passport Numbers of all these people. Her son was extremely agitated. He spoke that he nor the others do not have papers or Passport or identification with any of them. They are living under absolute sub-human conditions. Then, in an agitated manner, he said, 'Probably, I am talking to you for the last time.' And the phone got disconnected. Now, let us just imagine how these people are passing there day-after-day and it is going to be two months almost on the 8th of August.

I feel, the hon. Minister, along with the Government of Kerala Mr. Oomman Chandi worked in unison and were able to free 46 nurses who were held captive in Iraq there. The entire Parliament -- Lok Sabha and Rajya Sabha -- congratulated them for this united effort. But, we should know what is happening with these 40 people.

Sir, I have a few questions. The hon. Minister knows that these people who go out and seek work in all these countries, particularly in the West Asian countries, are really eking out a hand-to-mouth existence. They go out with the hope that they would be able to sustain their families. But, they are, firstly, cheated by unscrupulous travel agents. They sell their lands. They mortgage their houses to go there. They have no other way of sustaining themselves as they are economically weak. If whereabouts of these people are not known, I would like to ask the hon. Minister, through you, what forward movement has taken place. Have we been able to contact any of the travel agents who were responsible for a large number of these people to leave about 10 months ago?

[SHRIMATI AMBIKA SONI]

Some of them left a year-and-a-half before. But, the majority of these forty mostly from Punjab particularly went ten months ago. What has happened to those travel agents? Are these captive people getting their money back? Are these travel agents paying their money back? I have the names of some travel agents who, probably by the Ministry of Indian Overseas Affairs, were blacklisted but are now operating from another country. They have been given visas by this company which has employed these forty people, mostly from Punjab; I go on repeating. But, Iraq government they gave them blank visas for 600 people to recruit for this construction company. These Indians, who are operating from a friendly country, have the liberty to recruit and have the confidence of the construction company in Iraq, who had employed our citizens. Has any contact been made with them? At least some kind of a bulletin by the spokesperson of the Ministry of External Affairs should come out regularly. Since 17th July, when I mentioned about this stared question in Rajya sabha, until today, not a word has come out about these forty Indians.

Daily newspapers in Punjab do bring out some kind of story or other which they get from somewhere. This morning's newspaper talks about 46 people who have come *via* Kuwait and they have given some very heart-rending stories about the treatment they received. There have been other clippings from newspapers from Punjab, which talk of some people who have sighted these forty Indians who are held captive. They are supposed to be working like coolies carrying asla, arms, backwards and forwards. If these stories are coming out, and when there is no contradiction, and when there is no positive news alongside, then you can imagine how the people are feeling.

There is a country called Israel which is bombing schools, hospitals and areas where the civilian population lives because three of their nationals tourists were unfortunately or accidentally killed. Ignoring world opinion, ignoring the U.N. Resolutions, they go on bombing the Gaza strip! (*Time-bell rings*) No, Sir; I am sorry, I can't stop because I have two-three other points to raise.

Here, we have forty people and we are not being able to reassure their families. I asked the question about the travel agents. The name of the company is Tariq Noor Udha and the proprietor's name is Abu Abdullah, the man who can get from the Foreign Office 600 visas at a time. Have we contacted him? His General Manager, who also has a power of attorney for this company, who also lays down conditions of what pay they are going to get, how long they are going to work, the conditions of work, etc. Have we contacted them? I am sure we have. I am sure. But, something must come out so that one will feel reassured. If these people have the contacts and the influence to get so many blank visas, surely they can help us identify where these people are held. Sir, there is another thing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your time is over.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, never mind; we waited for one month. Two more minutes, please.

I want to ask the hon. Minister, through you, Sir. What are the other countries involved? Are there nationals of other countries involved in this? If there are, have we made any common cause with them? I know, the hon. Minister invited Ambassadors of West Asian countries. That was a good forward movement. But, it can't rest over there. There should be a flurry of activities. Our special envoys should be going to Saudi Arabia. Our special envoys should be going to Iran. The American Secretary of State was here. The Foreign Minister had some very important talk with him. I am glad that she talked on one or two important subjects also, which came in the Press. Did the Foreign Minister raise the issue of the Indians held captive in Iraq and could we get some help from him?

You had been to Bangladesh. There were several Bangladesh workers working along with these forty. They have been allowed to go back. Good for them. They have been allowed to go back. But, have we talked to the Bangladesh authorities when the Foreign Minister went there? Sir, I would also like to say that these people are in a very bad economic condition. I know that the Foreign Minister replied that that is the job of the State Government to look after their rehabilitation. It is true. But the State Government, in my State of Punjab, is part of the Union Government. I want to tell you, Sir, that they promised to give, at least, ₹ 20,000 a month, to all those families whose children have not yet come back. Some of them have been given, but many have not been given. It is two months since that promise was made. Sir, ₹ 20,000 per month was promised; it was not a one-time payment. Sir, I want to know from the hon. Minister as to what is being done for these people to pay back loans. The Foreign Minister has set up a very big Crisis Management Group and I compliment her for that. But more than that, has she thought of setting up a special group under the Overseas Indian Ministry, which will look after the affairs of Indians working abroad, study the contracts under which they go, keep in touch with the agencies which send them there, and every two or three months, have a visit to those camps where these people are virtually kept as prisoners in the constructions sites or wherever? That would, at least, put...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Ambikaji, please cooperate.

SHRIMATI AMBIKA SONI: Sir, I hardly speak. So, I would like to know if she considers putting up, on a permanent basis, a group which would look after just the Indians working in all these countries and the conditions they are working under and to see to it that their contracts are fulfilled.

[SHRIMATI AMBIKA SONI]

Sir, I also know that because of the advisories issued by the Foreign Office, lots of Indians have come back. ...(*Time-bell rings*)... They have lost their means of livelihood. Is it possible for this special group, if it is set up, and in the absence of this group, the Embassy, to take care of them in other adjoining countries? Can these people be accommodated in other adjoining countries, instead of being sent back, so that they can carry on their profession?

Sir, there is a very important thing which I would like to mention. In answer to a question on 22nd of this month, where an hon. Member of Parliament had asked, 'how many Indians are in foreign country jails?' A very detailed answer was given. But the name of Iraq was not mentioned. Sir, I have details with me that for the last two-and-a-half years, six Indians, at least, I know of these six boys who are from Punjab, are in an Iraqi prison. Sir, they are there for the last two-and-a-half years. I have their names and their passport numbers with me. This issue has also to be dealt with as a separate question because this information was not given in answer to a starred question, but I would like to ask of the hon. Minister as to why we are not getting, at least, these six Indians released. Thank you, Sir.

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, a major offensive in Northern Iraq against the Iraqi Government started on 8th June, but the Ministry issued its first travel advisory only on 15th of June. I would like to know as to why this delay was.

Sir, the Ministry also advised Indian nationals to leave Iraq by commercial means. However, this might not be possible for many of the workers as their passports are already confiscated by their employers and they lack the means to buy a ticket to come back. So, without any support, the Government has asked these people to come back on their own. It is not possible for many of the people employed in other countries to do so. We all are aware of the way they are treated, the way they are employed and the way they have to live over there. They are practically treated like slaves in many countries. According to the Government estimates, 22,000 Indians were in Iraq at the onset of this conflict. The actual numbers must be definitely more than this because we know that many workers migrate to these countries illegally and they do not have all the required papers with them. So, there must be many more people stranded over there. I want to know whether the Government is aware of the number of people who have actually been stranded there. Of course, this issue was also raised here. I would like to know as to what has happened to 41 Indian nationals who have been taken as captives by an unidentified group. What has become their state?

Sir, in response to a question raised by me on 24th July, 2014, the Minister has

given the following answer. "During the last three years, 751 complaints against illegal agents were received in the Ministry of Overseas Indian Affairs. However, prosecution sanction has been sought only in 30 cases." Why is this happening?

According to a survey conducted by the Centre for Development Studies in Trivandrum, only 8 per cent of the return migrants had been migrated through certified recruiting agents. We understand that more than half of the migrants who go to other countries are actually going through these illegal agents. A lot of these people pledge their only house that they have or all their lifetime savings in order to go and work over there through these illegal agents who do not take any responsibility for them. We have all come across many cases when the workers go there, their passports are taken away. They do not come back. They do not have proper job. They do not have places to stay which are clean and hygienic. Like sardines they are packed into a small room where eight to ten people have to stay. It is absolutely inhuman condition which they live in. So, what is the Government actually planning to do on a long-term basis to stop all this and actually make it more legal and better for the workers who go to other countries and protect them from illegal agents? In the answer given, the Government itself has admitted that only 30 cases were sanctioned for prosecution out of 750 complaints against these illegal agents.

One more important thing that I would like to raise is that on June 2, 2014, Rev Alexis Prem Kumar, a Catholic priest from Tamil Nadu was abducted in Afghanistan. The Government has failed to secure his release even after two months. We would like to know what has happened and if the Government has any information about this person. What are they doing to get him back? Thank you, Sir.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): Sir, it is a very serious issue. I share the views expressed by my senior Member of Parliament, Ambika Soniji. I come from the State of Kerala. One-fourth of our State's domestic product is contributed by the non-resident Keralites. Hundreds of nurses are working in Iraq. Lakhs of people are working in Gulf countries. We met the External Affairs Minister, I think, on June 23. I myself and the leader of CPI (M) in Lok Sabha, Shri Karunakaran, met the Minister and submitted a detailed memorandum. She took it very seriously. But even till today we have not got any written reply from the Minister with regard to the action taken by the Ministry. I think we were the first delegation. The Minister told us directly, "You are the first delegation who has come personally to us." But up till today, we have not got any written reply with regard to the steps taken and the other details in this connection.

Sir, as per this reply, 'an estimated 22,000 Indians were in Iraq'. Actually, we do not have the actual figures as to how many numbers are working in Iraq and other countries.

[SHRI P. RAJEEVE]
Is the Government thinking of making any changes in the immigration laws? Actually, there was a serious demand because this is an outdated immigration law. It should be looked into and amended to address the objective realities prevailing in the world today. Is the Government ready for that? This is one query, Sir.

As per this report, it is true that 46 nurses working in a local hospital in the city of Tikrit were taken to Mosul. The Government has taken a very good initiative and did a very good work. But as per the media report, a Malayali businessman had coordination with the Kerala Government and they did all these things and the Ministry was only providing aircraft and other facilities for doing it. That was the initiative of the Government of Kerala and the Malayali businessman because still another 41 Indian nationals working in a construction company in Mosul, who were taken captive by an unidentified group, we are not aware about their status. They are comparing this with it. It has happened because of this businessman and the initiative taken by the Government of Kerala and not by the Government of India. I want to know what is the actual position in this regard. Then, as hon. Member Shrimati Kanimozhi said, some sponsors are not ready to give back their passports. These are under their custody. What steps has our embassy taken in this regard? Our embassy, in Iraq, actually is not having sufficient staff. Have you deployed sufficient staff there to deal with the situation? What steps have been taken by the Ministry to evacuate all the Indians, working in Iraq at different places? Of course, some places are not facing any problems. But anything can happen any day. So, what steps have been taken by the Government to evacuate all the Indians there? Are you contemplating to give free air tickets or providing free chartered Air India flights for the purpose of evacuating Indian citizens from Iraq?

Then, what are your plans regarding rehabilitation? It is a very serious issue. Many of them have taken lakhs of rupees as Education Loans. They have to pay back their loan, with interest. But they are in the trap. What steps are you contemplating for their rehabilitation?

Then, another important issue. One Malyali died in Libya, yesterday. And, two Malyalis died in Afghanistan. Such serious things have happened because there is serious dilution of our Foreign Policy. Actually they are following a dual Foreign Policy. Smt. Ambika Soni correctly mentioned that for Gaza we fought maximum to get an opportunity to discuss the issue in this House (*Time-bell rings*) but the Government is not ready to condemn that issue. But in the BRIC countries, the Prime Minister was a signatory and the UNHRC specifically stated the name of Israel. The Council strongly condemns the failure of Israel. And, India voted in favour of that. But the Government is not ready to condemn. It is a dual Foreign Policy of the Government.

...(*Time-bell rings*)... Just last point. Actually the Foreign Policy is just the extension of Government's domestic policy. The domestic policy is to protect the interests of the Indian citizens who are working abroad, but we are following a policy that is hostile to the Arab countries. And, we are in trouble. I would like to request the Government to revisit their policies. Are you ready to condemn this attack on Gaza by Israel? With these words, I conclude, Sir.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय विदेश मंत्री जी, मैं आपको थोड़ी बधाई भी दे दूँगा, जो आप इस तरीके से इराक से तमाम नर्सों को वापस लाये। आप चौंकी होंगी कि मैं बधाई दे रहा हूँ। हम आपके अच्छे कार्यों की तारीफ भी करेंगे, लेकिन जहां कमियां होंगीं, वहां दर्पण भी दिखाएँगे, आईना भी दिखाएँगे और अपनी बातों को रखेंगे।

मैंने आपका स्टेटमेंट पढ़ा। ठीक है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी 41 लोग जो किडनैप कर लिए गए, उनकी जान के बारे में कुछ पता नहीं है। आपने क्लियर नहीं किया कि वे जिन्दा हैं या नहीं। यही बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, जो आपने कहा कि किडनैप कर लिए गए। तो देश पहले यह जानना चाहता है कि वे 41 लोग जिन्दा हैं या नहीं ?

दूसरा, आपके कैम्प के माध्यम से वहां जो 22 हजार इंडियंस रह रहे हैं, उनमें से कितने लोगों को टिकट मिला और कितने लोगों को वहां अन्य सुविधाएँ मिलीं, जो हम सुविधाओं की बात कर रहे हैं कि इम्मीग्रेशन वगैरह की सुविधाएँ मिलीं, जो हम सुविधाओं की बात कर रहे हैं कि इम्मीग्रेशन वगैरह की सुविधाएँ एम्बैसी के माध्यम से उन्हें दी जा रही हैं, तो आखिर ये कितने लोगों को मिली हैं ? यह तो पता लगे कि कितने लोगों ने माँगा और कितने लोगों को मिला तथा उस खर्चे को भारत सरकार ने वहन किया या वे लोग स्वंय अपने खर्चे को वहन कर के आ रहे हैं ? अगर उनके पास खर्च के लिए पैसा नहीं है, तो आप आज सदन में घोषणा करिए कि भारत सरकार नें नीति बनाई है कि इराक और लीबिया या विश्व के अन्य पार्ट में जो भारतीय फँसे हैं, अगर वे देश में वापस आएँगे, तो उनका खर्चा सरकार वहन करेगी। आप बड़ा दिल दिखाइए, क्योंकि अभी हमारे देश की विदेश नीति ही डिक्लेयर नहीं है।

मैं मानता हूँ कि आप प्रधान मंत्री जी के साथ नेपाल इस कारण से नहीं गई कि आज सदन में आपको जवाब देना था। लेकिन संदेश यह जा रहा है कि प्रधान मंत्री जी और विदेश मंत्री में कही मतभेद है। वे आपको ब्रिक्स सम्मेलन में भी अपने साथ नहीं ने गए और जब काठमाडूं गए, तब भी अपने साथ नहीं ले गए। तो अगर हमारी विदेश नीति के बारे में यह संदेश जाएगा, तो कहीं न कहीं हम गम्भीर रूप से नहीं लिए जाएँगे। हम सब के प्रधान मंत्री और आपके नेता जब गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तो अमेरिका ने उनको वीज़ा देने से मना कर दिया था। तब यूपीए की सरकार थी। कोई भी सरकार हो, लेकिन आज जब वे प्रधान मंत्री बन गए हैं, तो फौरन यूएसए ने कह दिया कि हां, हम वीज़ा लिए आपके दरवाजे पर खड़े हैं। यूके आपको कितनी गम्भीरता से ले रहा है ? अगर हम लंदन जाने का या यूके जाने का वीज़ा लेना चाहें, तो मुख्य मंत्री हों या गर्वनर हों, हमें उनकी एम्बेसी जाना पड़ेगा। हमें उनकी एम्बैसी जाना पड़ेगा। अगर हम एमपीज़ हैं और हम उनसे वीजा मांग रहे हैं, हमारा डिप्लोमैटिक पासपोर्ट भी है और अगर हम डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर भी वीज़ा मांग रहे हैं, तो वे कहते हैं कि आप हमारी एम्बैसी आइए, हमारे क्वैश्चन्स का जवाब दीजिए, इन्टरव्यू में शामिल होइए।

[श्री नरेश अग्रवाल]

जब मैंने वहां पर बड़े-बड़े गवनर्स को देखा, तब मैं चौंक गया। मैंने वहां पर दो गवनर्स से पूछा कि आप यहां क्यों आए हैं ? उन्होंने कहा कि हमको भी कम्पलसरी आना पड़ रहा है, क्योंकि यूके की वीज़ा नीति है कि जब तक व्यक्गित रूप से उपस्थिति नहीं होंगे, तब तक वीज़ा नहीं मिलेगा। इसको गंभीरता से कहां लिया गया ?

इंदिरा जी के नेतृत्व में यही देश 107 देश का नेतृत्व करता था, आप लोगों को भी याद होगा। हम गुटनिरपेक्ष बने थे औंर पूरे विश्व को भारत लीड करता था। आज आप हमको इतना बता दीजिए कि हिन्दुस्तान के साथ कितने राष्ट्र हैं ? नेपाल, बर्मा भी आपके साथ है या नहीं है, बंगला देश को तो छोड़ ही दीजिए ? सिर्फ इतना बता दीजिए कि नेपाल और बर्मा हमारे साथ है या नहीं है ? आखिर ऐसी कमजोरी क्यों है, ऐसी क्या कमजोरी है, हम कहां पर इतना कमजोर हुए ? हमारी विदेश नीति क्यों कमजोर है, हमारी विल पॉवर क्यों कमजोर है, जिसके कारण विश्व हमको गंभीरता से नहीं ले रहा है ?

चीन के बाद दुनिया की नम्बर दो की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हम हिन्दुस्तानी हैं। आज चीन पूरे विश्व पर छा गया है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Naresh*ji*, it is not a discussion on foreign affairs.

श्री नरेश अग्रवाल: श्रीमन्, मैं उसी से संबधित बात कह रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति: आपको सिर्फ प्रश्न पूछना है।

श्री नरेश अग्रवाल: श्रीमन्, मैं कोई दूसरा इश्यू नहीं ले रहा हूँ। मैंने उसी से जुड़े मुद्दे को उठाया है, वीजा इमिग्रेशन उसी से जुड़ा है। मैं कही केरल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने केरल की नर्सों की बात कर ली, लेकिन मैं कंट्री की ही बात कर रहा हूँ कि आखिर इसका क्या कारण है ? श्रीमन्, अगर पिछली परिचर्या पर नहीं जाएंगे, पूरे कारणों पर नहीं जाएंगे, तो फिर सुषमा जी भी बोल्डली जवाब नहीं देंगी और आप मत डरिए, जैसे सरकार में सब लोग डरे हुए हैं। सुषमा जी, आप सही स्टेप लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन कम से कम सदन में आज आप जवाब दीजिए, जिससे पूरे विश्व में एक संदेश जाना चाहिए कि हिन्दुस्तान बलशाली है, हिन्दुस्तान की विल पॉवर है, हमारी अपनी नीति है, नहीं तो विश्व के अन्य हिस्सों में जिस तरीके से हिन्दुस्तान के लोगों को बेइज्ज़त किया जा रहा है आज भी हम लोग अमेरिका में चले जाएं, तो वहां पर किसी के कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर के साथ क्या हो रहा है ...(**समय की घंटी**)... मैं चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो कम से कम आप एक संदेश जरूर दें कि सरकार ...(**समय की घंटी**)... उसकी अपनी नीति है और देश उनके साथ है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Sir, the first question I would like to ask is: What is the total number of Indians stranded in Iraq? There are conflicting numbers. It is good that about 4,900 Indians have been assisted to come back, but out of how many? It is important to know that. I shall be extremely happy if the Government could give an answer to this.

Secondly, Sir, there are construction labourers from Murshidabad, Malda, North Dinajpur, Nadia and North 24 Parganas districts of West Bengal in Iraq. In fact, according to the latest information that I have, most of the family members are not in touch with those who have gone abroad. In fact, they are in an absolute misery to know what has happened to them. So, I would like the Government to take measures to bring those 4,900 Indians back. What will happen to the rest? Many of them do not have their passports with them because the agents keep the passports with them. Many of them do not have money with them, because it is the agents who pay the money to take them there and also to bring them back. So, they are just stranded like beggars in a foreign country. Sir, I would urge, through you, to the Government to bring them back with an appropriate financial help, so that they reach their near and dear ones. We are deeply concerned, particularly, about the construction labourers. They have gone not only to earn their living, that they have done, but they have also done many things for the other country. Iraq Railways would not have run but for the Indian Railway workers. The Iraq Roadways would not have been there but for the Indian construction workers. So, it is not that they go there only to earn, but they are also contributing to their welfare. So, I would request the Government to take the matter very seriously, which they have done, and bring back all the Indians who want to come back. Thank you.

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, there are several lakhs of Indian workers working in Middle East as well as in North Africa. It is their foreign exchange remittances which is keeping Indian economy going in to an extent. Unfortunately, after the war broke out in Iraq, many of them are to be repatriated. Now, I would like to ask the Government – based on her statement – certain questions and seek the Government's response also.

One is, the plight of the returnees is quite miserable. I would like to ask the Government whether the Government will consider giving some ex gratia financial relief to all such workers who were repatriated midway through their contracts. Such workers who are in war zones and who have to return – maybe, against their will also in some cases – must be given financial compensation. This is number one.

Number two, whether the Government will consider giving insurance cover to all Indian workers who face such unusual and cruel situations in their lives. There is no such insurance scheme for Indian workers. Everything goes very casual and *ad hoc* Will the Government consider this issue?

Thirdly, the Government and the Ministry of Overseas Indian Affairs must keep in contact with such returnees and, in fact, find employment and placements for them or see if there is any possibility of it because they have come. But once peace returns to that region, peace returns to Iraq or West Asia, whether the Government will help the returnees to find the jobs and placements when there is a possibility. Nothing of this

[SHRI D. RAJA]
nature has been thought of. But the Government will have to apply its mind. You have repatriated but what happens to their life in the coming days? How will they take care of their living? So, this is one issue which the Government should consider.

Sir, I understand that the Government tries its best to repatriate the workers but still there are people who are yet to be repatriated, safeguarded. The Government will have to take care of this.

Finally, Sir, I also join Shrimati Kanimozhi on one issue, that is, on the issue of Father Alexis Prem Kumar from Tamil Nadu. He was abducted in Afghanistan, not in Iraq. He was abducted in Afghanistan on 2nd June, 2014. I understand the family of Father Alexis Prem Kumar met the External Affairs Minister and they have made the representation also. I do not know what is happening in this case, whether the Government was able to or has been able to find some breakthrough to find out where he is and what efforts the Government is making to get back Father Prem Kumar. I think, it is not a question of whether he belongs to this State or that State. But he is an Indian, a Catholic Father who has gone there on some humanitarian work, and he has been abducted in Afghanistan. Now it is the responsibility of the Government to see what best efforts it can make to trace him and get him back.

So, I hope the External Affairs Minister will respond to some of these issues. Thank you.

श्री के.सी. त्यागी: उपसभापति महोदय, इराक़ पर जब सन् 1990 में अमेरिका की तरफ से पहला हमला हुआ था, तब हम और आप, दोनों उस सदन में थे और बहन सुषमा जी शायद इस सदन में थी। उस समय इराक़ पर बड़े बुश ने जो हमला किया था, उसकी निन्दा उस सदन में आलॅ पार्टीज़ की तरफ से की गई थी। तब हिन्दुस्तान की विदेश नीति का वह एक जमाना था। नेता प्रतिपक्ष को यह ध्यान होगा कि उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी अपनी जान का खतरा मोल लेकर सद्दाम हुसैन और सरकार की सोलिडैरिटी के लिए इराक़ गए थे। अब इन 20-22 वर्षों में इतनी दुनिया बदल गई कि इराक के सद्दाम हुसैन भी गए, लीबिया के गद्दाफी गए, अयातुल्ला खुमानी के खिलाफ भी अमेरिका ने तमाम साजिशें की। दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान में पिछले 15-20 वर्षों से अमेरिका है। तो जहां इन नर्सों के और मजदूरों के निकालने का सवाल है, इस हर बीमारी के पीछे आपको अमेरिका मिलेगा। उसको लेकर इस सदन में, उस सदन में कभी कोई चर्चा नहीं होती। ऐसा दौर आया, क्या दौर था 1971 का । 60 दिन तक जो भुट्टो हिन्दुस्तान की सात पीढ़ियों से लड़ने की घोषणा करता था, यू.एन.ओ. में डेली आकर के आधे घंटे आंसू बहाया करता था कि बचाओ-बचाओ। लेकिन उस समय सोवियत संघ था। सोवियत संघ का विघटन और अमेरिका की पश्चिम एशिया में* दोनों एक साथ की घटनाएं हैं। इसलिए उसका जिक्र नहीं करोगे तो यह कहानी अधूरी होगी। 1990 के बाद जब बड़े बुश ने हमला किया, हम तटस्थ होकर के नहीं सक्रिय होकर के उनके साथ थे। दोबारा जब हमला हुआ, हम शांत थे और तिबारा जब हमला हो रहा है, अब वहां इराक बचा ही नहीं है, उसके तीन

* Expunged as ordered by the Chair.

हिस्से हो गए। सीरिया बचा ही नहीं है, उसके दो हिस्से हो गए और पूरा पश्चिम एशिया जहां से 55 हजार करोड़ रुपए हर साल मेरे दोस्त पी. राजीव के राज्य में आते हैं, उस पश्चिम एशिया की आज यह हालत हो गई। इसमें दर्जनों सवाल जुड़े हुए हैं, समय आपने कम दिया है। एक तो सुषमा जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितनी भी ये मैनपॉवर एजेंसीज हैं, आज शाम को इन सब के लाइसेंस कैंसिल कीजिए, यह भ्रष्टाचार का, लोगों को लूटने का सबसे बड़ा अड्डा हैं। जितनी भी वहां नर्सें गई हुई हैं, मैं बहुत कष्ट के साथ आपको कहना चाहता हूं, मैंने कल रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इराक का कम्युनीक पढ़ा है। शायद वे 40 आदमी बचे नहीं हैं। उनमें से जो एक आदमी बचकर आया है, उसने रिपोर्ट दी है कि जिस समय मैं उनके काफिले में से निकलकर गिरा हूं, मेरे ऊपर इतनी लाशें गिर गई थी कि उसी की वजह से मैं आज बच पाया तो यह जो रेड क्रॉस सोसाइटी का बयान है, मैं उसको अंडर एस्टीमेट नहीं करता, नम्बर-वन। नम्बर-2, वहां पर समूचे पश्चिम एशिया में इराक समेत, मैं कोई आलोचना के तौर पर नहीं कहना चाहता, मेरे दो दोस्त बैठे हुए हैं, राजीव शुक्ल जी और डी.पी. त्रिपाठी जी, इन्दिरा जी ने चुनाव हारने के बाद राजस्थान के उस समय के जो मुख्य मंत्री थे भैरों सिंह शेखावत जी, ये दोनों गवाह हैं, तीसरे दोस्त हैं नहीं हमारे बीच में, उन्होंने बुला करके भैरों सिंह शेखावत जी को बताया कि ये-ये चीजें हैं। जो पाकिस्तान से लगे हुए बॉर्डर के साथ आप लोग कर सकते हो। तो यह जो डिप्लोमेसी थी वह पूरे देश की, दुनिया की एक हुआ करती थी। जो मेरी जानकारियां हैं, सुषमा जी के बेस्ट एफर्ट्स के साथ, कि उन्होंने हमारे अली अनवर साहब के कहने से भी सऊदी अरब से ...(**व्यवधान**)... मगर जिस तरह से एफर्ट्स होने चाहिए थे विपक्ष के लोगों के साथ बात करके। ...(**समय की घन्टी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put the question. प्रश्न पूछिए। Put the question.

श्री के.सी. त्यागी : एम.के. नारायनन साहब हैं, जो सऊदिया अरब के प्रिंस के व्यक्तिगत दोस्त हैं, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : प्रश्न पूछिए।

श्री के.सी. त्यागी : तो मेरा यह कहना है कि एम.के. नारायनन को आप इसमें एंगेज कर सकते थे, कुछ और ऐसी संस्थाओं को भी आप इसमें एंगेज कर सकते थे। आज माफ कीजिएगा, जब से इजरायल और फिलिस्तीन के मामले में हमने तटस्थता दिखाई है, तब से पूरे पश्चिमी एशिया में हमारी साख घटी है जो कभी इतनी खराब नहीं हुई और उसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई दिक्कत भारत पर आए, एक मुल्क भी आपके साथ खडा हो गया, इससे भी खतरा पैदा हो गया। पूरा पश्चिम एशिया इस समय संघर्ष में है, अमेरिका जो चाहता है, जब चाहता है, जहां चाहता है वहां करता है लेकिन यह इन्दिरा जी और राजीव गांधी जी के बाद कांग्रेस भी बदल गई और आप तो पहले ही से बदले हुए थे। आप तो 1971 में इण्डो-सोवियत ट्रीटी के खिलाफ थे। जिसको लेकर के इन्दिरा जी ने पूरी दुनिया में अपनी विदेश नीति का झंडा गाड़ा था। तो अब मैं यह कहना चाहता हूं कि रिलीफ के तौर पर जो वर्कर्स हैं आपके क्या चैनल हैं, आप बेहतर जानते होंगे, सउदी अरेबिया भी अमेरिका के साथ है। जॉर्डन सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ है। तो वहां पर जो विकल्प हो सकते हैं, जो बहुत कम बचे है, उन चैनल्स को खोल करके इन मजदूरों के साथ आप इनको बाहर निकालने का काम कीजिए। मेरी जो जानकारियां हैं, जो नर्सें वहां पर हैं और जो ज्यादातर दक्षिण भारतीय क्रिश्चियन्स हैं, उसमें उन्होंने अपनी तकलीफें बताई हैं, इल्लीगल एम्प्लायॉमेंट एग्रीमेन्ट है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें

[श्री के.सी. त्यागी]

से 15 से लेकर 18 घंटे काम करना पड़ता है ...(**समय की घन्टी**)... सर मैं खत्म कर रहा हूं। उनके पासपोर्ट वहां जब्त कर लिए गए हैं। सर, इस समय जो नर्सेज वहां शार्ट-टर्म वीज़ा पर गई हुई हैं, उनके वीजा की अवधि खत्म हो गई है। इसके लिए उन पर 500 डॉलर्स का जुर्माना लगता है। जबकि उनकी तनख्वाह सिर्फ 600 डॉलर्स है। वे वहां घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। इसलिए उनको वहां से लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सर, नर्सों ने भारत सरकार से सम्पर्क किया है। आप कहें तो मैं दो तीन नर्सों के बयान यहां पढ़कर सुना सकता हूं जिसमें उन्होंने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की भर्त्सना की है।

श्री उपसभापति :* अनपार्लियामेंटरी है, इसे कार्यवाही से निकाल दें। आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। You are not asking questions and you are delaying.

SHRI K.C. TYAGI: But, Sir, this is the present position of West Asia.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: See, I have names of a dozen more Members. Please sit down.

श्री के.सी. त्यागी : सर, आपने समय बहुत कम दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I know. I have to manage the time.

श्री के.सी. त्यागी : सर, यह बहुत बड़ी क्राइसिस है।

श्री उपसभापति : आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं। आप खुद जानते हैं। मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री के.सी. त्यागी : सर, वहां एक तारिक नूर अलहुदा कंस्ट्रक्शन कम्पनी है। उसका मालिक तीन सौ-चार सौ मजदूरों को यहां से ले गया। वह इनसे दो से पांच लाख रुपए पर-हेड तक चला गया और वहां जाकर उसने उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। वे लोग वहां बॉंडेड लेबर्स की तरह काम कर रहे हैं।

श्री उपसभापति : त्यागी जी, प्लीज समाप्त कीजिए। I am unable to control, what can I do?

श्री के.सी. त्यागी : सर, मेरा यह कहना है कि जब तक सरकार पश्चिम एशिया के बारे में अपनी नीति स्पष्ट नहीं करेगी और एग्रेसर और जिसके ऊपर एग्रेसन हुआ है, उनमें भेद नहीं करेगी...

श्री उपसभापति : आप ये सब बातें मत करिए ।

श्री के.सी. त्यागी : तब तक न वहां से मजदूरों के वापस आने की संभावना है, न नर्सों के आने की संभावना है और न यहां से इन लोगों के वहां रोजगार पर जाने की ही संभावना है, धन्यवाद ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri D.P. Tripathi. See, the names, which were included in the notice, are over. Now, I am allowing some more Members because the subject is very important. So, I will give each Member only two minutes. ...(*Interruptions*)... I have said that I am allowing but I will give only two minutes to each Member. That's all.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री डी.पी. त्रिपाठी (महाराष्ट्र): सर, इस से अच्छा होता कि आप टाइम ही न देते। The subject is very important. Sir, I have always obeyed your orders. But, I am sorry to say that anyone, who follows discipline and dignity, is not allowed even two sentences to speak when he raises his or her hand in this august House. I want to put this on record. I will follow your orders.

Sir, the matter is very important. This is the Calling Attention on the plight of Indians stranded in Iraq raised by the hon. Member, Shrimati Ambika Soni. The condition in Iraq, is very complicated because the number of people stranded is not exactly available with the Government or with the Ministry of External Affairs. This is not their fault. I am not criticizing the Government or the Minister of External Affairs. As a matter of fact, they should be congratulated for the hard work and the continuous attention that they have given to the problems of trapped Indian nationals in Iraq, Libya, Syria and everywhere. And, I am not saying this; the hon. Chief Minister of Kerala, Mr. Oommen Chandy, has said that the External Affairs Minister, Mrs. Sushma Swaraj, was available to him at 2.00 a.m. and 3.00 a.m. on the problems of the nurses stranded there. This kind of concentration for helping the Indian nationals is really admirable. The number of Indian nationals, as I said, stranded in Iraq is a big problem because many of them have gone illegally, as Mr. K.C.Tyagi was pointing out, through the manpower agencies *via* Dubai. They are not listed by our Missions either. This is the problem.

Secondly, the point, which has not been mentioned by any hon. Member here, is about hundreds of Shias who are living in Najaf and Karbala. It is considered most pious for Shia Muslims to be buried in Karbala. One of the members of the Nawab Rampur family was also buried in Karbala. I know this personally. So, that is the problem.

Then, I talked to some office bearers of the Punjabi Welfare Society, Kuwait. There are 55 Punjabi youth who are trapped in Iraq who have no passports, no documents and no money. The local people are asking for 25,000 dollars per person to repatriate them to India or allow them to travel to India. This is a big problem. The Punjabi Welfare Association, Kuwait has collected funds and they want to help them.

Next problem is, Libya. Syria, of course, you all know; I am not going into that. The Government is aware of it and the House has discussed this. Hon. Leader of the Opposition, while participating in the debate on West Asia, had elaborately explained the situation there. (*Time-bell-rings*) Sir, give me one minute more. In Libya, roughly the number of trapped people was 18,000. Our Government is making all efforts to bring those Indians to the borders of Tunisia, and, from there, get them back to the country.

Now, I come to the final point of why this is happening in West Asia, in Iraq, Libya, Syria, and, Gaza, which was mentioned by hon. Member, Ambika*ji*. This is because our consistent policy has been to make the West Asia the 'Best Asia'. This has been India's policy. (*Time-bell rings*)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That's all.

SHRI D.P. TRIPATHI: No, no. Sir. Let me say something. Sir, the big powers and Israel are determined to make the West Asia as 'Waste Asia'. This is the problem.

Finally, Sir, while concluding, I will quote the great Palestinian poet, Mahmoud Darwish, who was great interpreter of exile captivity and helplessness and atrocities against the people, who used the vocabulary of pain and struggle. He says, "Sister, there are tears in my throat and there is fire in my eyes." (*Time-bell rings*) Let me complete, Sir.

Mahmoud Darwish is a great Palestinian poet. Don't dishonor his poems. ...(*Interruptions*)... He says, "Sister, there are tears in my throat and there is fire in my eyes, I am free. No more shall I protest at the Sultan's Gate. All who have died, all who shall die at the Gate of Day, have embraced me, have made of me a weapon." This is from a 'Diary of a Palestinian Wound'.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Now, you please conclude.

SHRI D.P. TRIPATHI: And, remember ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, you please sit down.

SHRI D. P. TRIPATHI: And, remember, hon. Members of this House, those who make weapon of a man are real heroes ...(*Time-bell rings*)... Therefore, the attack by Israel on Gaza, which is causing turmoil in the entire West Asia, will be fought, and, finally, a few lines from Faiz:

"जिस ज़मीं पर भी खुला था मेरे लहू का परचम,
लहलहाता है वहां अरज़े फलस्तीं का अलम।
तेरी अदा ने किया एक फलस्तीं बरबाद,
मेरे ज़ख्मों ने किए कितने फलस्तीं आबाद।"

धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Tripathi*ji*, I agree that very precious words are coming out from the mouth of hon. Members. But time-constraint is there. I am not able to go and pick them up. What do I do? One hour is already over. I have, at least, more than seven or eight names. The point is that I received all these names only later. I am ready to cooperate but my request is to please adhere to the limit of two minutes. I am ready to allow everybody but please cooperate with me. Now, Shri Mukhtar Abbas Naqvi.

3.00 P.M.

श्री मुख्तार अब्बास नकवी (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, इराक में जो कुछ हो रहा है, निश्चित तौर से वहां केवल इंसान ही नहीं मर रहे हैं बल्कि इंसानियत का भी कत्लेआम हो रहा है। ऐसे हालात में जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं या फंसे हुए थे, उनको सरकार द्वारा संवेदनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ, मज़बूती के साथ उनकी सुरक्षा और उनको भारत लाने के सारे प्रयास और प्रयत्न करना, इसके लिए निश्चित तौर से मोदी जी की सरकार और विशेष तौर पर हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज इसके लिए बधाई की पात्र हैं। महोदय, अब तक लगभग पांच हजार से ज्यादा लोग सुरक्षित तौर से भारत वापस आ चुके हैं, उसके लिए, जैसा सुषमा जी ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जो प्रयास सरकार ने किए, जो कोशिशें की ...(**व्यवधान**)...

† **جناب مختار عباس نقوی (اتر پردیش)** : اپ سبھا پتی مہودے، عراق میں جو کچھہ ہو رہا ہے، نشچت طور سے وہاں کیول انسان ہی نہیں مر رہے ہیں بلکہ انسانیت کا بھی قتل عام ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں جو بھارتی وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں یا پھنسے ہوئے تھے، ان کو سرکار دوارا سنویدن-شیلتا کے ساتھہ، ایمانداری کے ساتھہ، مضبوطی کے ساتھہ ان کی سرکشا اور ان کو بھارت لانے کے سارے پریاس اور پریتن کرنا، اس کے لئے نشچت طور سے مودی جی کی سرکار اور وشیش طور پربھاری ودیش منتری شریمتی سشما سوراج بدھائی کی پاتر ہیں۔ مہودے، اب تک لگ بھگ پانچ ہزار سے زیادہ لوگ سرکشت طور سے بھارت واپس ا چکے ہیں، اس کے لئے، جیسا سشما جی نے اپنی استیتمینٹ میں کہا کہ جو پریاس سرکار نے کئے، جو کوششیں کیں ...(مداخلت)...

श्री डी.पी. त्रिपाठी: 4,900 हैं।

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: त्रिपाठी जी, मैंने लगभग 5000 कहां । अगर आप उससे संतुष्ट हैं तो मैं 4,900 कह देता हूं। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि सरकार ने जिस संवेदनशीलता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जिस मज़बूती के साथ, जो लोग वहां फंसे हैं, उनको वापस लाने में और जो लोग वहां पर अभी भी हैं, उनमें यह विश्वास पैदा करने की कोशिश की कि सरकार मज़बूती के साथ उनके साथ है, उनकी सुरक्षा के प्रति चिंतित है और उनको भारत लाने के लिए वह गंभीरता और मज़बूती से प्रयास कर रही है, वह सराहनीय है। नजफ़ में, बकरा में, करबला में इसके लिए विशेष कैम्प लगाए गए। निश्चित तौर से यह पहली बार होगा कि इस तरह की घटना, जिससे पूरा इराक और इराक के इर्द-गिर्द पूरा देश खून की होली खेल रहा हो, चौतरफा हिंसा हो रही हो—वहां बच्चे मारे जा रहे हैं, बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं—लाश के ढेर पड़े हों, उस माहौल में, उस दौरान भारत के लोगों में यह एहसास कराना कि वे सुरक्षित हैं और सरकार उनके प्रति संवेदनशील है और उन्हें वापस ला रही है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं सरकार को और विशेष तौर पर विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को बधाई देता हूं। महोदय, मैं अपनी बात इसी से खत्म करूंगा कि बार-बार यह बात सामने आयी कि वहां पर कुछ ऐसे भारतीय भी फंसे हुए हैं, जिनके डाक्युमेंट्स नहीं हैं और अगर हैं भी तो वहां पर जो एजेंसीज़ हैं या वे लोग, जो उन लोगों को रोज़गार देते हैं, उन लोगों ने उनके डाक्युमेंट्स को अपने कब्ज़े में ले रखा है, इसलिए वे यहां वापस आना चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं। उनके लिए विदेश मंत्रालय और माननीय विदेश मंत्री जी क्या प्रयास कर रही हैं ? धन्यवाद।

---

†Transliteration in Urdu script.

† **جناب مختار عباس نقوی :** ترپاٹھی جی، میں نے لگ بھگ 5000 کہا۔ اگر آپ اس سے سنتشٹھ ہیں تو میں 4،900 کہہ دیتا ہوں۔ اس سے بھی اہم یہ ہے کہ سرکار نے جس سنویدن-شیلتا کے ساتھ، جس ایمانداری کے ساتھ، جس مضبوطی کے ساتھ جو لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو واپس لانے میں اور جو لوگ وہاں پر ابھی بھی ہیں، ان میں یہ وشواس پیدا کرنے کی کوشش کی کہ سرکار مضبوطی کے ساتھ ان کے ساتھ ہیں، ان کی سرکشا کے پرتی چنتت ہے اور ان کو بھارت لانے کے لئے وہ گمبھیرتا اور مضبوطی سے پریاس کر رہی ہے، وہ سراہنے ہے۔ نجف میں، بغرا میں، کربلا میں اس کے لئےوشیش کمیپ لگانے گئے۔ نشچت طور سے یہ پہلی بار ہوگا کہ اس طرح کی گھٹنا، جس سے پورا عراق اور عراق کے ارد گرد پورا دیش خون کی ہولی کھیل رہا ہو، چوطرفہ ہنسا ہو رہی ہے، وہاں بچے مارے جا رہے ہیں، بزرگ مارے جا رہے ہیں، مہیلائیں ماری جا رہی ہیں، لاش کے ڈھیر پڑے ہوں، اس ماحول میں، اس دوران بھارت کے لوگوں میں یہ احساس کرانا کہ وہ سرکشت ہیں اور سرکار ان کے پرتی سنویدن-شیل ہے اور انہیں واپس لا رہی ہے، یہ اپنے آپ میں اہم ہے، اس کے لئے میں سرکار کی اور وشیش طور پر ودیش منتری شریمتی سشما سوراج کو بدھائی دیتا ہوں۔

مہودے، میں اپنی بات اسی سے ختم کروں گا کہ بار بار یہ بات سامنے آئی کہ وہاں پر کچھ ایسے بھارتی بھی پھنسے ہوئے ہیں، جن کے ڈاکیومینٹ نہیں ہیں اوراگر ہیں بھی تو وہاں پر جو ایجنسیز ہیں یا وہ لوگ، جو ان لوگوں کو روزگار دیتے ہیں، ان لوگوں نے ان کے ڈاکیومینٹس کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اس لئے وہ یہاں واپس آنا چاہتے ہوئے بھی نہیں آ پا رہے ہیں۔ ان کے لئے ودیش منتراليہ اور ماننے ودیش منتری جی کیا پریاس کر رہی ہیں؟ دھنیواد۔

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, I want to take the sense of the House. We can extend the time. There is no other way.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Discussion on the Ministry of Power will be the casualty. You should be aware of that. Now, Shri Brajesh Pathak. Not there. Shri Baishnab Parida. You have only two minutes.

SHRI BAISHNAB PARIDA (Odisha): Thank you, Sir, for allowing me to speak

†Transliteration in Urdu script.

a few words. Many Indians are stranded in the West Asian countries. It is a matter of great concern for our people and for us also. First of all, I appreciate the efforts which have been made particularly by the Foreign Minister to bring back the Indians from those troubled countries. But there are certain things which the people of this country want to know. How many Indians are still stranded there in the West Asian countries, particularly in Iraq, Libya and other countries? The second thing is, those who are coming back must be properly rehabilitated and compensated. The third thing is, the travel agents, those who have taken them to these countries, must be dealt with so that in future sending the Indians in this manner to these countries should not take place. Another thing which is apprehending us is, it is not clear how long it will take to settle the situation there. Keeping in view the India's relation and its trade, particularly oil, gas and other things, with those countries, our attitude towards those countries should be very clear. The people of our country want to know these things, Sir. Special envoys should be sent to those countries to find out who are stranded where and how they are living there. Recently, we read in some newspapers that in Saudi Arabia Indians were kept in toilets and tortured. We are not in a position to provide employment to everybody in our country. They are going to work in those countries and sending money to our people and our country. Indians should live there in dignity. That is the duty of our Government. My request to the Government is this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question and sit down.

SHRI BAISHNAB PARIDA: The Government should be very clear in its attitude towards West Asian countries where our people, who are stranded there, are suffering. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Mohammed Adeeb. He is not there. Shri Rajeev Shukla.

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): सर, सुषमा जी का वक्तव्य मैंने पूरा पढ़ा और उसमें यह बात स्पष्ट नहीं है कि जो मोसुल में 41 भारतीय हैं, उनमें से 31 पंजाब से हैं, कुछ हिमाचल से हैं, कुछ बिहार से हैं और कुछ देश के तमाम हिस्सों से हैं, उनके जीवन का क्या हुआ ? एक तो यह स्पष्टीकरण हो जाए कि वे जिंदा हैं या नहीं हैं ? दूसरी बात यह है कि जिस तरह का इमरजेंसी रिस्पांस होना चाहिए था, जितनी हमें उम्मीद थी उतना इमरजेंसी रिस्पांस नहीं हुआ। वह क्यों नहीं हुआ, उसके कारणों पर भी आप प्रकाश डालिए। तीसरी चीज यह है कि इसमें केरल गवर्नमेंट ने जितनी तत्परता दिखाई, उतनी तत्परता शायद पंजाब सरकार ने नहीं दिखाई। केरल सरकार की वजह से भारतीय नर्सें वहां से भारत में आई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उनके एक्सपीयरेंस सर्टिफिकेट नहीं मिल पाए हैं। इसके आलावा उनकी बहुत सेलेरी वहां पर बाकी है। एक्सपीरियेंस सर्टिफिकेट, सेलेरी उनको कैसे हासिल हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

जो लोग वहां से वापस आ रहे हैं, क्या उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम सरकार बना रही

[श्री राजीव शुक्ल]

है ? चूंकि उनकी नौकरी छूट गई, उनका वहां पर पैसा भी बकाया रह गया है, तो वे यहां आकर क्या करेंगे ? दूसरी बात यह है कि आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि भारतीयों को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी बैटलशिप भेज रहे हैं, यह बैटलशिप कब जा रहा है, कब आ रहा है, यह बैटलशिप जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, यह भी हम आपसे जानना चाहेंगे, इसके बारे में भी पता लगना चाहिए। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, जो कम्पनियां, कंस्ट्रक्शन कम्पनियां, उनको लेकर गई थीं, वे उनके पासपोर्ट वापस नहीं कर रही हैं। उनके पास ट्रेवल डाक्युमेंट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से वे लोग वहां पर फंसे हुए हैं। कम्पनियां उनके डाक्युमेंट्स को जमा कर लेती हैं और उनको वापस नहीं देती हैं, यह लोगों को वहां पर रोके रखने का तरीका है। ...(**समय की घंटी**)... आप ट्रेवल डाक्युमेंट्स एम्बेसी से उनके लिए बनवा रही हैं या नहीं बनवा रही हैं ? आपने लिखा है कि जो इंडियन कम्युनिटी का वेलफेयर फंड है, उसका काफी इस्तेमाल आप एयर टिकट्स वगैरह देने के लिए कर रही हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कितना इस फंड का इस्तेमाल हुआ है? कब तक सारे लोगों को टिकट्स और सारे डाक्युमेंट्स मिल जायेंगे, जो वहां से आना चाहते हैं? इन चार-पांच सवालों के उत्तर मैं आपसे जानना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अविनाश राय खन्ना (पंजाब): थैंक्यू सर। मैं यहां अम्बिका सोनी जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि वे भी होशियारपुर से है और मैं भी होशियारपुर से हूं और हमारे कम से कम दो हजार लोग वहां पर फंसे हुए हैं। मैं सुषमा जी का इसलिए धन्यवाद करता हूं, क्योंकि विदेश में जो लोग बैठे हुए हैं, मैं बहुत दिनों से उनके मुद्दे उठा रहा हूं। पहली बार एक ऐसा सिस्टम देखने को मिला कि दिल्ली में भी एक कंट्रोल रूम है और बगदाद में भी एक कंट्रोल रूम है। जो दिल्ली में कंट्रोल रूम है, उसमें जो अफसर डील कर रहे हैं, वे पंजाबी बोलने वाले हैं, पंजाबी समझने वाले हैं। इसी तरह से बगदाद में भी पंजाबी, मलयाली समझने वाले हैं। सुषमा जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि जितने भी फोन हमने किए, मेरे पास कम से कम रोज पांच-छह मैसेज़ आते हैं कि हमारा लड़का वहां फंसा हुआ है और इस कम्पनी में है, तो जो फोन नम्बर हम आपके कंट्रोल रूम में लिखाते थे और जो फोन नम्बर हम उनका देते थे, वहां पर आपका कंट्रोल रूम उनसे बात करके कोई इन्फॉरमेशन लेता था, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन यह विषय इतना आसान नहीं है। बहुत दिनों से लोग विदेशों में फंसे हुए हैं, कई लोगों का पता है और कई लोगों का पता नहीं है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्या हम कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर पाएंगे कि जो लोग बाहर जाते हैं, जो कम्पनी उनको लेकर जाती है, वह कम्पनी सही है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर तक आपको एक एजेंसी बनानी चाहिए। वह वैरिफिकेशन करके उन लोगों को यह बताए कि आप जिस कम्पनी में रहे हैं, यह कम्पनी लीगल है या नहीं हैं। दूसरी बात यह है, चूंकि इराक की बात हो रही है, तो आप हमें यह बताएं कि इराक में कितने लोग लीगल वे से गए हैं और कितने लोग डॉलर की चाह में इल्लीगल वे से गए हैं? जब तक हमें ऐसे देशों में लोगों के जाने के ट्रेंड के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक हम और आप इसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. All right.

श्री अविनाश राय खन्ना: आप से एक अंतिम निवेदन यह है कि ऐसी घटनाओं में जो लोग फंसे होते हैं, उनके लिए एक स्टडी ग्रुप बनाया जाए, ताकि कभी भी कोई ऐसी बात हो तो, immediately उन लोगों को लाया जा सके, आपको एक ऐसा प्रयास कराना होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI RAJEEV CHANDRASEKHAR (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, on July 4th, the extremist group, ISIS, released 46 Indian nurses after one week of captivity. While this represented the end of the ordeal for 46 Indian nurses and subsequently, five thousand other Indians, it has put the spotlight firmly on the condition of Indian labourers working in the Middle-East and the lack of institutional support that they get from the Government.

Sir, as my colleagues have said, there are over 70 lakh Indians in the Middle-East, remitting close to 30 billion US dollars. This is a significant amount and in today's globalized world, we must not stop our citizens from following whatever path they want to realise their dreams. But, Sir, the Middle-East dream must not become an Indian nightmare. As per media reports, several employers in these countries are forcing Indian employees and labourers to live under harsh, cruel, and sometimes, inhuman conditions. It is reported that in one country alone, in two years, as many as 500 workers have died and the Indian Embassy has not shared the details of these deaths or whether the victims' families have received compensation.

Sir, every Indian, rich or poor, is a son or a daughter of India and it is the duty of the Government of India to ensure his or her safety. Therefore, Sir, in the interest of thousands of Indian employees and labourers in the Middle-East countries, I would urge upon Sushmaji and the Government to adopt a three-pronged framework to ensure safety of our fellow citizens. First, there should be a better location accounting of all the Indians working in the Middle-East. Second, as Avinashji said, there should be stronger regulation of these employment agencies. Third, I would urge for bilateral treaties with the Gulf countries for safety, to protect and guarantee safety of our fellow citizens, including the Gulf Cooperation Council. Thank you, Sir.

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमन् मैं माननीय मंत्री जी से केवल दो-तीन सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल तो यह है कि क्या यह सच है कि मिडिल ईस्ट में लगभग 70 लाख भारतीय काम करते हैं और उनसे जो अर्निंग होती है, देश को जो remittance होती है, global remittance का जो लगभग 65 मिलियन डॉलर है, उसका आधे से ज्यादा है ?

दूसरी बात यह है कि क्या हिन्दुस्तान की पॉलिसी प्रारंभ से लेकर जो रही है, पिछले कुछ वर्षों से उसमें deviation हुआ है ? तो क्या मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की बात नहीं थी ? अगर थी, तो क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में युनाइटेड नेशन्स में मतदान करते समय कभी अमरीका के दबाव में आकर अमरीका के साथ वोट किया, कभी abstain किया और कभी मिडल ईस्ट के aggrieved नेशन्स थे, उनके पक्ष में वोट किया। कुल सात बार वोटिंग हुई, जिसमें तीन बार abstention, दो बार पक्ष में और दो बार खिलाफ वोटिंग हुई। यह deviation क्या हमारी विदेश नीति में बदलाव का संकेत नहीं है?

तीसरी बात यह है कि अमरीका ने पहले सोवियत यूनियन में जब हस्तक्षेप किया था, तो विद्रोहियों

[प्रो. राम गोपाल यादव]

को हथियार दिए, तालिबान के रूप में सारी दुनिया को उन्हें भेदना पड़ा। सीरिया में असद के खिलाफ जिन विद्रोहियों को हथियार दिए जा रहे हैं, क्या वे अमरीका द्वारा नहीं दिए जा रहे हैं ? क्या सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों को मिलाकर ISIS संगठन ने नई इस्लामिक स्टेट बनाने की घोषणा की है, क्या यह घोषणा इन्हीं हथियारों के बल पर नहीं हो रही है? अगर यह घोषणा हो रही है, तो जो हमारे मित्र देश रहे हैं, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है और जहां से हमें सत्तर प्रतिशत ऑयल मिलता है, अगर यह हो रहा है, तो फिर इस मामले में हम उस देश के लिए बोलने तक की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं ? क्या हमें अमरीका, रूस या चीन का डर है ? क्या बात है, इसका क्या कारण है ? गद्दाफी का लीबिया खत्म हो गया, लेकिन याद रखिए कि जब लीबिया खत्म हुआ, तब भी अकेला हिंदुस्तान का वॉरशिप ऐसा था, जिसको लीबिया ने अपने पानी में जाने की इजाजत दी थी, जबकि अमरीका, रूस और अन्य किसी देश के युद्धपोत को त्रिपोली के वाटर में जाने की इजाजत नहीं दी थी। ये हमारे उनके साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं। हमारे इराक, ईरान और लीबिया, सभी से अच्छे रिश्ते रहे हैं। यहां तक भी होता रहा है कि जब हिंदुस्तान के लोग वहां जाते हैं तो काहिरा से लेकर बगदाद तक ...(**समय की घंटी**)... मैं केवल सवाल पूछ रहा हूं, काहिरा से लेकर बगदाद तक जब विजिटर्स को मालूम पड़ता है कि ये हिंदुस्तान से, अलहिंद से आए हैं, अगर वे कुछ खाते-पीते या कुछ खरीदते हैं, तो वे उनको कंसेशन देते हैं। उन लोगों का हमारे प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर है। जब हमारी मिडिल-ईस्ट के देशों के लिए हमेशा प्रो पॉलिसी रही है, तो फिर क्या कारण है कि हमारी इस पॉलिसी में बदलाव आ रहा है ? मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही कंपीटेन्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं और इस पर अपनी नीति को स्पष्ट करेंगी।

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to know whether the Government recognises that it is only because of the huge reservoir of goodwill built up over the last seven decades with all West Asian and North African countries, Monarchist or Republican, Revolutionary or Islamist to which Dr. Najma Heptulla , the Minister of Minority Affairs, has been witness and was one of the most articulate exponents, when she was on our side? I would also like to know whether they understand that it is because of this huge reservoir of goodwill that we were able to secure massive West Asian support in rescuing not only our 46 nurses from Mosul, but also those Indians who were held up against their will in the Iran-Iraq War of the 1980s, the First Gulf War of 1999, the Second Gulf War of the early years of this decade, as also in Lebanon, Egypt, Tunisia and above all Libya. And do they accept this? Therefore, do they understand that to retain and further build up on the accumulated goodwill our new Government would have to give priority to our political and diplomatic relations with all West Asian and North African countries that has not been in evidence ever since the President's Address completely ignored the West Asian Region? In this regard, whether the Government understands that it is the issue of Palestine that united all Arab countries whatever their differences are, and who have never forgotten the contribution of India to the Palestine cause from Jawaharlal Nehru, to Indira Gandhi, to

Rajiv Gandhi down to the 21st century. But now I am getting extremely concerned as the new Government's foot is dragging which is putting our friendship with the Arabs in jeopardy and thereby jeopardising now and in future the millions of Indian workers who are working in the most turbulent region of the world. Is it not that this that accounts for the initial success we had with the nurses when the Arabs believed that the new Government would maintain continuity in our Palestine policy? With regard to these 40 or so Punjabi workers who are not being released is it because the Government has failed to inspire confidence in the Arab world on the Palestinian policy from what it used to be. I would like the Government to answer all these four questions.

श्री माजीद मेमन (महाराष्ट्र): ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, इत्तेफाक से हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यहां मौजूद हैं। इनकी रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 में इन्होंने कहा है कि इराक में 22,000 भारतीय नागरिक कंफ्लिक्ट में फँसे हैं, जिनमें से आगे चल कर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब तक इन्होंने 4,900 लोगों को मुक्त करवाया है। नतीजे के हिसाब के मुताबिक 17,100 भारतीय नागरिक आज भी इराक में फँसे हुए हैं। मैं माननीया मंत्री जी को याद दिलाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम यह न भूलें कि अगर ये 17,100 भारतीय नागरिक, जो आज की तारीख में, आपने 2 अगस्त बताया है, आज 4 अगस्त को हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, वहां फंसे हुए हैं, तो ये आपके ऑफिशियल ऑकड़े हैं। अनऑफिशियल आँकड़े इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा कि अगर वह इन 17,100 भारतीय नागरिकों का स्टेटवाइज ब्रेक अप बताए, तो हम लोग हर स्टेट के मुख्य मंत्री के जरिए भी उनकी सहायता के लिए कोशिश कर सकते हैं कि उनके लिए तुरंत क्या मदद की जा सकती है। यह न भूला जाए कि ये 17,100 लोग हमारे देश के गरीब लोग हैं। ये वहां कोई तफरीह के लिए नहीं गए थे। ये यहां गरीबी से बेजार होकर नौकरी ढूँढने के लिए सैकड़ों-हजारों मील दूर अपने मां-बाप को छोड़ कर, अपने वतन को छोड़ कर वहां मजबूरन गए थे। उनकी मजबूरी, उनकी गरीबी का हमें एहसास करना होगा और उनको जिस किस्म की सहायता चाहिए, मॉनिटरी असिस्टेंस चाहिए, वह उन्हें मुहैया कराना हमारा फ़र्ज़ बनता है। ये एक ख्वाब लेकर गए थे कि ये कुछ पैसे कमा कर आएँगे। बदकिस्मती से हम सबका यह अनुभव है कि जब ये लोग जाते हैं, तो एजेंट्स के मार्फत जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई सोर्स नहीं होता, कोई इंफ्लुएंस नहीं होता। ये एक ख्वाब लेकर जाते हैं, लेकिन जब ये वहां जाते हैं, तो इनके सारे पासपोर्ट अननोन स्पांसर्स के पास रख दिए जाते हैं। ...(**समय की घंटी**)... Ninety per cent of such people have no communication...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question.

श्री माजीद मेमन: मैं इनके सामने सिर्फ दो सुझाव रखना चाहता हूँ। मंत्री महोदया से मेरी यह विनती है कि a Control Room should start operating with regular bulletin every day, telling what is the position every day till the last Indian is rescued. Secondly, please inform the House कि अब ये जो 17,100 लोग हैं, क्या ये लोग हमारे संपर्क में हैं या उनके पास इतनी सहायता भी नहीं है कि वे अपने रिश्तेदारों से या सरकार से संपर्क कर सकें ? मैं यह चाहूँगा कि इसकी गम्भीरता को देखते हुए हम इस पर बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे काम करें। धन्यवाद।

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, Shrimati Ambika Soni has raised this issue today, which is causing a lot of disquiet in Punjab because there is no information about the forty of our boys, who have been captured there for the last many weeks. At the same time, I would like to thank and express the gratitude on behalf of the Government of Punjab and the people of Punjab to the hon. Minister, Shrimati Sushma Swaraj. She has met the families more than three times. She has been encouraging them. She has been giving them hope and information. I am sure with her perseverance, very soon, we will be able to get our boys home. But the broader point is, as many of my friends said, there are more than seven million people working abroad and many of them are being exploited. So, I feel it is high time that the Government of India took two or three steps. First, Grievance and Assistance Cells should be set up in every Embassy abroad which should be manned by a large number of our officers, including a legal cell, so that those of our countrymen who are caught there or are being exploited, can get some help immediately. Secondly, this House will have to debate that stringent laws need to be enacted to punish these middlemen, touts or the so-called employment agents who are leading our young boys astray. No.3 is, as Mr. Raja Said, some kind of insurance is required. So, I would suggest that the Government creates a kind of sinking fund where every person, who is going abroad, contributes, maybe, 5 dollars or 10 dollars a month, and the money goes into that sinking fund. Then that fund can be utilized to help those who are in distress. Thank you.

श्री अश्विनी कुमार (पंजाब): उपसभापति जी, आज हम सबके समक्ष एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा आया है, जिस पर हम सदन में चर्चा कर रहे हैं। सुषमा जी ने अपने वक्तव्य में हमें कई बातें बताई हैं। जहां तक सरकार की पहलकदमी का सवाल है, जहां-जहां भी हमारे फंसे हुए भारतवासियों को मदद मिली है, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये कदम पर्याप्त हैं ?

हमें यह मालूम है कि 22,000 में से करीब 5,000 लोगों को वापस आने में हमने सहायता दी है, मगर बाकी जो लोग वहां फंसे हैं, उनके मुताल्लिक आपके वक्तव्य में कोई चर्चा नहीं है। आपने सिर्फ 41 लोगों के बारे में बात की है, जिनमें से 31 लोग पंजाब से है, जहां से मैं आता हूं। पंजाब में ऐसे बहुत से परिवार हैं, जो अहुत ही दु:ख का, मजबूरी का सामना कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जिनकी चर्चा आपके जवाब में नहीं है, जो वहां गैर-कानूनी तरीके से गए हैं, मगर भारतीय हैं। उनकी वापसी कैसे होगी, आगे भविष्य में हम उनकी रक्षा के लिए क्या कर सकेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको चिन्तन करना होगा।

मैं आपसे तीन सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि हमने अपने मुल्क में कोई ऐसा दल बनाया है, जिसको हम किन्हीं खास सिचुएशंस में रैपिड ऐक्शन फोर्स की तरह यूज़ कर सकें ? जहां तक वैस्ट एशिया का सवाल है, तो यह सिर्फ इराक की बात नहीं, लीबिया की बात है, लेबनान की बात है, सीरिया की बात है, पूरे खाड़ी देशों की बात है, जहां पिछले कई सालों से बहुत चिन्ताजनक स्थिति उत्पन्न हो रही है। इराक और कुवैत के पहले वॉर में भी हमने लाखों लोगों की mass evacuation की थी। आज हमें यह बताया जा रहा है कि शायद आप mass evacuation इसलिए

नहीं कर सके, क्योंकि जितनी तेजी से ISIS वालों ने हमले किए, उसका किसी को अनुमान ही नहीं था। क्या आने वाले समय में हम अपनी ओर से इस तरह की इंटेलिजेंस सुनिश्चित कर सकेंगे, ताकि हमको पहले से पता हो और हम अपने लोगों की mass evacuation कर सकें ? हम सारे भारतवासियों को वहां से निकाल नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर foreign exchange remittance आ रहा है। उनके परिवार वहां रहते हैं। लेकिन अगर हम पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर बात करें, तो यह देश के लिए बहुत चिन्ता का विषय है।

आपके वक्तव्य में एक बात और कही गई कि हम किनसे बात करें, यह भी किसी काम मालूम नहीं है। आज एक मुश्किल यह है कि भारत सरकार किससे बात कर रही है ? क्या हम अरब लीग की लीडरशिप से बात कर रहे हैं या हम यूएन की किसी ऑर्गनाइज़ेशन से बात कर रहे हैं? सऊदी अरब के साथ खास तौर पर हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं और जिसका इस इलाके में बहुत असर भी है, क्या उनसे बात हो रही है ? बहुत से सद्दाम हुसैन के फॉलोअर्स हैं, जिनके साथ हमारे अच्छे रिश्ते थे, क्या उनके लोगों से बात हो रही है ? क्या उन लोगों से बात हो रही है, जो बहुत बड़े पैमाने पर ISIS वालों की प्राइवेट फंडिंग कर रहे हैं? इन लोगों के साथ बात करके ही हम कोई सार्थक पहलकदमी कर पाएंगे।

मैं आपसे ये चन्द सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि आने वाले समय में इस तरह की स्थितियों से जूझने के लिए हमारी रणनीति क्या होगी, इसके लिए यह बहुत जरूरी होगा।

आखिर में मैं आपसे यह बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह का वक्तव्य आपने लोक सभा में दिया, करीब-करीब वही वक्तव्य आपने यहां भी दोहराया। जून से अगस्त के तीन महीनों में, जैसा कि आपने कहा कि आपने इतनी पहलकदमी की, उसके बावजूद स्थिति वहीं की वहीं हैं। हजारों लोग वहां फंसे हुए हैं। सही बात क्या है, वह देश के सामने पूरी तरह से नहीं आ सकी। क्या आने वाले दिनों आप देश के सामने पूरी जानकारी रखेंगी, यही मेरा सवाल है। धन्यवाद।

SHRI V.P. SINGH BADNORE (Rajasthan): Sir, before I come to the main issue, I must acknowledge the fact that the Minister has been burning the midnight oil and putting in all efforts for the repatriation of stranded workers. My question is a very specific one. In the statement, she has said that 4,900 workers have been brought back and, out of them, 3,900 have been provided air tickets. There is a problem because all the aerodromes are also surrounded, and there are problems of landing. The battles are raging on the north side of Iraq. Sir, my specific question is: Can you press the Indian Navy also to help us out, because everybody knows that these landing ships that we have in our Navy, with helicopters, with hospital facilities? Can that be also pressed in? It is because that would be on the South side where there are no battles raging. Is that a possibility? Have you thought about it or can you do something on that also? Please reply to me. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Did you give your name early, Shri Sukhendu Sekhar Roy?

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Yes, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: But I did not see the name.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): We had given two notices, one from Shri Derek O'Brien and another from Shri D. Bandyopadhyay. Shri Bandyopadhyay has already spoken. Shri Derek was not here and I had given my name much earlier.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is news to me! But anyhow you put the question. That is all. Now I cannot accept any more names.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY : Sir, before seeking clarifications, I would like to clarify that I don't have any inference on leading question and I shall concentrate on Iraq only. On behalf of All India Trinamool Congress, while I join the hon. Members in expressing our deep concern and anguish over the developments in Iraq, I would like to know from the hon. Minister for External Affairs, one, the exact number of Indians who are stranded in Iraq as of now; two, whether there is any nurse still stranded in Iraq and out of the Indians who are stranded in Iraq, how many of them are still kept as captives. Lastly, could the Government tell this House how soon it would be in a position to ensure the safe return of Indian workers to our country ?

श्रीमती सुषमा स्वराज: उपसभापति जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आज सुबह मुझे यह लग रहा था कि व्यवधान के कारण यह चर्चा खत्म हो गई है, क्योंकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नियम यह कहता है कि अगर आपने एक बार स्टेटमेंट ले कर दिया तो उसको ओवर एंड आउट कहते हैं, फिर वह दोबारा नहीं हो सकती और अगर एक विषय सदन के सत्र में एक बार आ जाए, तो दोबारा नहीं उठाया जा सकता। मुझे अच्छा लगा कि आपने नियमों में ढील देकर इस चर्चा की अनुमति दी, क्योंकि मैंने जो भाषण सुने, उनमें बहुत सी इतनी मिथ्या धारणाएँ व्यक्त की गई हैं कि कम से कम अपने उत्तर में मैं उनको स्पष्ट कर सकूँगी और स्थिति को साफ कर सकूँगी।

अम्बिका सोनी जी ने चर्चा शुरू करते हुए कहा कि उन्होंने मेरा लोक सभा का वक्तव्य भी पढ़ा है और राज्य सभा वाला भी पढ़ा है, लेकिन दोनों में कोई अन्तर नहीं है, केवल एक आंकड़े का फर्क है। अम्बिका जी, आप तो स्वयं मंत्री रही हैं, अगर दोनों में अन्तर हो, तब तो विषय बनता है, लेकिन अगर दोनों में अन्तर न हो, तब विषय नहीं बनता है, क्योंकि जब मैं एक ही विषय पर दोनों सदनों में वक्तव्य दे रही हूँ तो दोनों सदनों में समान बात ही रखूँगी। बहुत बार अलग-अलग बात कह दी जाती है, तो विषय बन जाता है कि लोक सभा में तो आपने यह कहा और राज्य सभा में आप यह कह रही हैं। लेकिन मैंने समान वक्तव्य दिया, एक आंकड़ा जरूर बदला और वह आंकड़ा इसलिए बदला, क्योंकि वह वक्तव्य 24 जुलाई का था, जिसका आपने जिक्र किया कि मैंने आंकड़ा बदला। वह आंकड़ा बदलता जाएगा, हर दिन बदलता जाएगा।

अभी मुख्तार अब्बास नकवी भाई ने जब यह कहा कि 5000 ज्यादा लोग आ गए हैं, तो लोगों ने कहा कि इस पर तो 4900 लिखा है। 4900 लिखा है as of 2nd August. 2 अगस्त को 4900 लोग

आए और अगर आज वे यह कहते हैं कि 5000 से ज्यादा लोग आ गए, तो वह गलत नहीं है, क्योंकि उसमें और दो दिन का आंकड़ा जुड गया। वहां से हर दिन लोग आ रहे हैं, इसलिए दोनों सदनों में मैंने समान वक्तव्य दिया, क्योंकि मैं समान विषय पर बोल रही थी और यह आंकड़ा हर दिन बदल रहा है। मैंने जिन प्रश्नों के जवाब दिए, उनमें आंकड़ा कुछ और था, जो लोक सभा में जवाब दिए, उनमें आंकड़ा कुछ और था और आज जवाब दिया, उसमें 2 अगस्त का आंकड़ा है। लेकिन सबसे पहले मैं उस धारणा को ध्वस्त करना चाहती हूँ जो माजीद साहब ने कही। आप कह रहे हैं कि मैंने इसमें लिखा है कि 22 हजार लोग फंसे हुए हैं। नहीं, मैंने कहा है कि इराक में 22 हजार भारतीयों की संख्या है यानी 22 हजार भारतीय इराक में रहते हैं। वे सब के सब फंसे हुए नहीं हैं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इराक में रहने वाले, भारतीयों को हम तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं-एक है पूरी तरह सुरक्षित, दूसरे हैं बंधक और तीसरे हैं फंसे हुए। माजीद साहब, हमारा सौभाग्य है, मैंने जहां लिखा है कि 22 हजार में से 15 हजार कुर्दिस्तान में हैं, वे सारे के सारे सुरक्षित हैं। वहां कोई संघर्ष नहीं हो रहा और न होने की संभावना है, इसलिए सबसे पहले तो 22 हजार में से वह 15 हजार काट दीजिए, बचे केवल 7 हजार और उन 7 हजार में से 41 बंधक हैं। बंधक वे हैं, जिनसे हमारा संपर्क टूटा हुआ है। बहुत लोगों ने पूछा, आपने भी कहा कि क्या 17,100 से संपर्क है? अरे बाकी सबसे भी संपर्क है, केवल 41 बंधक हैं, जिनसे संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन प्रत्यक्ष संपर्क टूटा हुआ है, परोक्ष संपर्क अलग-अलग स्रोतों से उनसे है। इसलिए सबसे पहले तो यह धारणा मिटा दीजिए कि 22 हजार फंसे हुए हैं। 15 हजार तो कुर्दिस्तान में सुरक्षित हैं, 41 बंधक हैं और जो बाकी हैं, वे भी सारे फंसे हुए नहीं हैं। हम फंसे हुए किन्हें कहते हैं? जिनके बारे में बार-बार बात आ रही थी कि कंपनियों में काम करने के लिए गए, पासपोर्ट मालिकों ने रख लिए और अब वे आना चाहते हैं, तो कंपनियां उनको पासपोर्ट नहीं दे रहीं हैं। किसी के पास पासपोर्ट हैं, मगर आने का पैसा नहीं है और वे आना चाहते हैं, तो टिकट नहीं दे रहे हैं। ये जो 5 हजार लोग हम लाए हैं, इनमें से मात्र एक हजार लोग ऐसे हैं, जिनको कंपनियों ने टिकट दिए या जो स्वयं संपन्न थे, अपने टिकट लेकर आ गए। नरेश अग्रवाल जी ने सवाल सीधा मुझसे पूछा था, अगर आपने यह स्टेटमेंट पढ़ लिया होता, तो इसके पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि हमने 4,900 लोगों की सहायता की है, जिनमें से 3,938 को हमने एयर टिकट भी दिया है और दस्तावेज भी दिए हैं और ये कैसे दिए हैं, यह भी मैं बता दूं। आज से पहले यह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि लोग एम्बैसी में बैठ कर इंतजार करते थे कि जो आएगा, हम उसको मदद देंगे। हमने दूसरा तरीका अपनाया। हमने बगदाद के अलाव बसरा, नजफ और करबला में कैम्प ऑफिसेज़ खोले और जिन अधिकारियों को मैंने यहां से भेजा, उनको हमने यह ब्रीफ किया कि आप एम्बैसी में नहीं बैठेंगे, केवल हेल्प लाइन पर आने वाले फोन का इंतजार नहीं करेंगे, आप उन तमाम इंडियन कंपनीज़ में जाएंगे, जहां भारतीय काम कर रहे हैं। उनकी मीटिंग लेंगे और उनकी मीटिंग लेकर उनसे पूछेंगे, हो सकता है क्योंकि उस समय मुझे यह खबर आ रही थी कि कोई आना नहीं चाहता है, नेचुरली नौकरी के लिए गए हैं, जब तक लड़ाई सामने नहीं है, कोई आना नहीं चाहता, तो मैंने कहा, नहीं, आप उन्हें परसुएड करेंगे कि वे आएं और फिर कंपनियों से बात करेंगे। जो कंपनियां पासपोर्ट दे देगी, ठीक, जो पासपोर्ट नहीं देगी, उनको आप एमरजेंसी सार्टिफिकेट्स देकर या नए पासपोर्ट बना कर लेकर आएंगे। हजारों-हजार खाली पासपोर्ट की बुकलेट्स मैंने वहां पहुंचाई। राजीव शुक्ल जी पूछ रहे थे कि एमरजेंसी सर्टिफिकेट नर्सों को नहीं मिले, तो वे कैसे आईं? एमरजेंसी सर्टिफिकेट किसे कहते हैं? एमरजेंसी सर्टिफिकेट वह ट्रेवल डॉक्युमेंट है, जो पासपोर्ट के अभाव में दिया जाता है।

श्री राजीव शुक्ल: मैंने एक्सपीरिएंस सर्टिफिकेट के बारे में पूछा था। उन लोगों ने वहां पर जितने दिन नौकरी की, उसका एक्सपीरिएंस सर्टिफिकेट उनको नहीं मिला। अगर वह उनको मिल जाए, तो उसके आधार पर उन्हें नौकरी मिल जाए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: उस पर मैं बाद में आऊंगी। अभी मैं निकालने की बात कर रही हूँ, उस पर भी आती हूँ। जहां तक एमरजेंसी सर्टिफिकेट्स का सवाल है, यह जो 3,938 हमने लिखा, जिनके पास भी पासपोर्ट नहीं थे, हमने सबको पासपोर्ट मुहैया करवाए, एमरजेंसी सर्टिफिकेट्स देकर ट्रेवल डॉक्युमेंट्स दिए। जिस किसी के पास पैसा नहीं था, ये जो 3,938 हैं, इनको अपना पैसा देकर लाए हैं, इन सबको टिकट दिए और केवल वहीं तक टिकट नहीं दिए कि दिल्ली लाकर सबको छोड़ दिया। मैं नरेश भाई को बताना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था, वरना फिनैंशियल हेल्प दीजिए। बंदोपाध्याय जी ने कहा था कि फिनैंशियल हेल्प दीजिए। हम उन सबको टिकटें देकर जब दिल्ली लाए, तो दिल्ली में उनका सम्मान से स्वागत हो, उन्हें रिसीव किया जाए, इसके लिए जब उन्हें वहां जहाज में चढ़ाया जाता था, तब वहीं से हम पता कर लेते थे कि किस-किस राज्य के लोग चढ़ रहे हैं। उन-उन राज्यों के रेज़िडेंट कमिश्नर्स को कहते थे, मेरे अपने प्रवासी भारतीय कार्यालय के जो अधिकारी हैं, वे जाते थे और वे उनको रिसीव करते थे। हर रेजिडेंट कमिश्नर अपने प्रदेश के लोगों को लेकर अपने भवन में जाता था और फिर दोपहर में हमें यह बताता था कि उनमें से कितने हैदराबाद जाएंगे, कितने त्रिवेंद्रम जाएंगे, कितने कोच्चि जाएंगे, कितने पंजाब जाएंगे और कितने कलकाता जाएंगे। उनमें से एक-एक को हमने अपने-अपने प्रदेश तक जाने के एयर टिकट्स दिए हैं। यही नही, आप यह पूरी प्रक्रिया समझ लीजिए कि पहले हमारे आदमी वहां कंपनियों में गए, भारतीयों के साथ बैठक की, उसको परसुएड किया कि चलो, फिर जिनके पास पासपोर्ट्स नहीं थे, उनको पासपोर्ट्स दिए, जिनके पास पैसे नहीं थे उनको टिकट दिए, उसके बाद उन्हें दिल्ली लाकर, उनका स्वागत करके रेजिडेंट कमिश्नर्स के माध्यम से उनके भवनों में ठहराया। तब उन भवनों में जाकर उन्हें हमने टिकट पहुँचाए और यह कहा कि अब आप अपने-अपने प्रदेश में चले जाओ। इस तरह से यह इवैकुएशन हुआ है और 7,000 लोगों में से 5,000 लोग आए हैं तथा 2,000 वे लोग हैं जो आना नहीं चाहते, जिनको हम अभी भी परसुएड कर रहे हैं। हमारे यहां सबने कहना शुरू कर दिया, बसरा वाले ने कहा कि पिछले दो महीनों में टोटल 20 कॉल्स आई है, अब तो आप हमें वापस आने दीजिए, तो मैंने कहा कि नहीं, अभी आप रुक जाओ और वहां अभी और लोग जो रुके हैं उनको आप किसी तरह परसुएड करो। हम इस काम में बगदाद से भी लगे हैं। मैंने स्वयं कैरो के चीफ मिनिस्टर को फोन किया कि बगदाद की नर्सेज़ आने को तैयार नहीं हो रही हैं। जो लड़ाई मोसुल में हुई है, उससे बगदाद के हालात खराब हो सकते हैं, आप उनको फोन करके कहिए कि वे आएँ और अगर वे फिर भी नहीं आतीं तो हमें वे लिखकर दे दें कि हम आना नहीं चाहतीं, क्योंकि मैं कल को यह अपराध स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं होऊँगी कि वे वहां फँसी रह गईं और आपने उनको नहीं निकाला। इस तरह, हम तो यहां तक कह रहे हैं। मैं आप सब से कह रही हूँ कि आपके अपने-अपने राज्यों में, अगर आपका कोई जानकार है या अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी के परिवार वाले ने आपसे सम्पर्क किया है तो आप अपने-अपने राज्य के किसी व्यक्ति को यदि इराक से और मैं आज इसमें लीबिया भी जोड़ रही हूँ कि लीबिया से निकालना चाहते हैं, तो आप हमको सिर्फ सूची दे दें, मै आपको इस सदन में खड़े होकर आश्वस्त करती हूँ कि हम पासपोर्ट, पैसे या टिकट देकर भी उनको वहां से निकालकर लाएँगे।

नरेश भाई, आप पैसे की बात कर रहे हैं! जब मैं परसों अपनी कांस्टिटुएंसी में थी तो वहां मैसेज

गया कि बेंगाजी से लोगों को निकालने के लिए हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जो लोग बेंगाजी में फँसे हुए हैं, उनको वहां से फेरी के माध्यम से माल्टा लाना पड़ेगा, जहां से एयर इंडिया का जहाज उनको ले आएगा, मगर उस फेरी के लिए एक लाख रूपये प्रति पैसेंजर लगेंगे। तो मैंने कहा कि क्या आज का दिन पैसे गिनने का है? अरे, एक लाख लगेंगे या पाँच लाख लगें, तुम फेरी करो, मगर बेंगाजी से सब लोगों को माल्टा लेकर आओ ताकि एयर इडिंया का जहाज वहां जाकर उनको यहां ले आए। हम एक क्षण भी पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। अभी राजीव शुक्ल जी पूछ रहे थे कि आईसीडब्ल्यूएफ का कितना पैसा लग गया? अभी पैसे गिनने की फुर्सत कहां है? अभी तो पैसा लग रहा है, खर्चा हो रहा है और अब तो लीबिया में भी पैसा लगना शुरू हो गया। हमारे आसपास के जितने मिशंस हैं, हम सबका पैसा पहले बगदाद ट्रांसफर कर रहे थे, अब हम लीबिया में भी ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण किसी एक व्यक्ति को वहां फँसा हुआ नहीं रहने दिया जाएगा। मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आप जिन लोगों की भी लिस्ट हमको देगें कि ये लोग आना चाहते हैं तो वे सारे के सारे आएँगे, यह मैं आपको बता रही हूँ।

अब बात उन 41 लोगों की है। जहां तक उन 41 लोगों का प्रश्न है, इसे अम्बिका जी ने उठाया, उस बारे में गुजराल जी ने भी बात की तथा अश्विनी कुमार जी ने भी बात की। नैचुरली, आप पंजाब से हैं और मैं आपकी चिन्ता समझ सकती हूँ, लेकिन मैं आपको यहां खड़े होकर बता रही हूँ कि हमारा उनसे कोई डायरेक्ट सम्पर्क नहीं है, यह मैं स्वीकार करती हूँ। अगर उनसे सम्पर्क होता तो वे बंधक क्यों होते ? आदमी तभी कैप्टिव होता है जब उसका सम्पर्क टूट जाता है, लेकिन एक नहीं, बल्कि अनेक स्रोतों से हमने यह पता लगाया है और उन स्रोतों के हवाले से मैं यहां पर खड़े होकर जिम्मेदारी से यह कहना चाहती हूँ कि वे जीवित भी हैं और कुशल भी हैं।

मुझे दु:ख हुआ कि यहां भाई के.सी. त्यागी ने एक रेड क्रेसेंट का हवाला देकर कहा कि वे नहीं रहे, यह अच्छी बात नहीं है। ...(**व्यवधान**)... पहली बात तो मैं यह कहूँ कि यह असत्य है और दूसरा, मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस तरह के समय में अफवाहों का बाजार बहुत गर्म होता है। हम लोग अफवाहों पर न जाएँ। जब सरकारी सोर्स आपको कुछ कहे तो उस पर भरोसा करें, उस पर विश्वास करें। अम्बिका जी, ये जो 41 लोग हैं, इनके परिवारों से मैं एक-दो बार नहीं बल्कि तीन-तीन बार मिली हूँ और डेढ़-डेढ़, दो-दो घंटे तक मिली हूँ। आप जो कह रही हैं, चुंकि हरसिमरत कौर बादल जी ने मेरे साथ मिनिस्टर की शपथ ली है, गोपनीयता की शपथ ली है, इसलिए वे पेपर्स मैं उनके साथ शेयर कर सकती थी तथा किसी और के साथ मैं शेयर नहीं कर सकती थी। मैंने उनको वे पेपर्स भी दिखाए हैं, जिनके आधार पर हम कह रहे हैं कि वे जीवित हैं और कुशल हैं। श्री भगवंत मान आप पार्टी के एमपी है। वे मुझसे मिलने के लिए आए थे। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको कागज नहीं दिखा सकती, क्योंकि आपने गोपनीयता की शपथ नहीं ली है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। नरेश गुजराल जी तीन बार आए मेरे पास। किसी ने यह कहा कि केरल के मुख्य मंत्री ने तो बहुत प्रो-एक्टिव होकर उनको निकाल लिया। पंजाब के मुख्य मंत्री ने क्या किया, पंजाब के मुख्य मंत्री ने कोई काम नहीं किया। पंजाब के मुख्य मंत्री मुझे स्वंय दो बार मिलने आए, सुखबीर बादल जी मुझे मिलने दो बार आए। पूरा शिरोमणि अकाली दल का जत्था मुझे मिलने आया और यहां के जो पंजाब के एम.पीज. हैं, वे सारे के सारे मुझे मिलने आए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर। शायद बी.जे.पी. वाले तो कम थे, क्योंकि यहीं पकड़ लेते थे। अविनाश राय खन्ना जी तो मुझे आते-जाते कॉरिडोर में पकड़ लेते थे। कॉरिडोर में मुझसे पूछते थे, मेरे कक्ष में आकर के पूछते थे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने यह चिंता

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

न जताई हो। यह चिंता जताई है। लेकिन मुझे दुख हुआ जब पी. राजीव जी ने यह कहा कि वह तो एक मलयाली व्यापारी निकालकर आ गया। यही एक बात के.सी. त्यागी जी ने भी कही थी। मैं फिर कहना चाहती हूं कि मुझे उस मलयाली व्यापारी का नाम तो बतला दो ...(**व्यवधान**)...

SHRI P. RAJEEVE: That is in newspapers.

श्री सुषमा स्वराज: यह सिरे से गलत है, सिरे से गलत है। मैं नहीं जानती कि कौन है वह मलयाली व्यापारी और अगर मलयाली व्यापारी इतना सक्षम है तो फिर वह क्यों पैरोकियल हो रहा है? अगर उसने नर्सेज निकालीं, तो मेरे ये 41 लोग भी निकलवा दे, मैं उसको पद्मश्री दिलवा दूंगी, यहां खड़े होकर कहती हूं। लाओ तो, कौन है वह मलयाली व्यापारी जो नर्सेज को निकाल कर ले आया, वह इन 41 लोगों को भी निकाले, क्योंकि मैं ...(**व्यवधान**)...

SHRI P. RAJEEVE: Madam, it is in newspapers.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैंने अभी कहा कि न्यूजपेपर पर मत जाइए। वह न्यूजपेपर वाला मुझे बताए कि कौन है वह मलयाली व्यापारी, जो नर्सेज को निकाल कर लाया है। बेवजह की अफवाहें चल रही हैं। मैं यहां खड़े होकर कहती हूं कि जितने लोग इराक में हैं ...(**व्यवधान**)...

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, why are you angry at Malayalee?

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: No, no; it is *vyapari* ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She is saying '*vyapari*' ...(*Interruptions*)... It is *vyapari* ...(*Interruptions*)... She is speaking '*vyapari*'.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: I am not angry with Malayalees. मैं जितने लोग निकाल कर लायी हूं उनमें मलयाली सबसे ज्यादा हैं। I love them. अभी भी लीबिया से जितने निकाल रही हूं उनमें भी मलयाली सबसे ज्यादा हैं I love them. I am saying about the 'trader'. They are saying that a Malayalee trader who brought them back.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI GHULAM NABI AZAD): It is being said.

श्रीमती सुषमा स्वराज: इसलिए मैं यह कह रही हूं, क्योंकि मैं जब यहां खड़े होकर के इराक में फंसे भारतीयों की बात करती हूं, तो तमिल, तेलुगू, मलयाली, पंजाबी के रूप में नहीं करती, वे सब भारतीय हैं। तो अगर कोई मलयाली व्यापारी मलयालियों को निकालने के लिए बाहर आया तो मैं कहती हूं कि भैया, पंजाबियों को भी निकाल ला। लेकिन ये बातें बिल्कुल गलत हैं। रही बात इसकी कि आपकी बातें किससे हो रही हैं, अश्विनी कुमार जी ने मुझसे चार-पांच जगहों के नाम ले दिए कि क्या उनसे बात हो रही है? बाकी कुछ लोगों ने भी कहा। यहां बहुत सीजंड लोग बैठे हैं, पूर्व प्रधान मंत्री जी के समेत। वे जानते हैं कि जब इस तरह का कोई प्रोसेस होता है, तो उसका मूल सिद्धांत होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है गोपनीयता, सीक्रेसी। अगर मैं उसको बाहर कर दूं तो प्लान ही प्लान रह जाएगा फिर एक्शन नहीं होगा। जो आप कह रहे हैं कि एक्शन प्लान बतला दो, इनमें एक्शन प्लान नहीं बताए जाते। मैं इतना कह सकती हूं कि अश्विनी कुमार जी, आपने जितने नाम लिए हैं, उन

सबसे बात हुई है और मैं जिम्मेदारी से कह रही हूं। अरब देशों की बात बहुत बार आई, मणि शंकर अय्यर जी ने भी कही। सारे के सारे विदेश मंत्रियों से मैंने व्यक्तिगत तौर पर बात की है। खाड़ी के सारे एम्बैसेडर जो यहां हैं, उनको बुलाकर बात की है अपने एम्बैसेडर जो खाड़ी में हैं, उनको बुलाकर बात की है और केवल खाड़ी के देश नहीं, जो बाकी देशों का भी आपने नाम लिया कि वे सहायक हो सकते हैं, वे सहायक हो सकते हैं, उन सबसे बात की है। मैंने वह हर दरवाजा खटखटाया है जो दरवाजा अगर खुल जाए तो हमारे बच्चे बाहर वापस आ जाएं। हर दरवाजा खटखटाया है। बीच में खुल जाए तो हमारे बच्चे बाहर वापस आ जाएं। हर दरवाजा खटखटाया है। बीच में खबर यह आई थी कि ईद के दिन या ईद के एकाध-दो दिन बाद छोड़े जा रहे हैं। अभी तक वह संभव नहीं हुआ। मैं तो इंतजार कर रही हूं, इस तरह से इंतजार कर रही हूं जैसे मां अपने बेटे का इंतजार करती है। मैं चाहती हूं कि वे 41 बच्चे इसी तरह आ जाएं जैसे 46 नर्सेज आईं। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं कि जिस दिन उनको भी उनके घर पहुंचवा सकूंगी। इसलिए यह मत कहिए। मैंने हर वह दरवाजा खटखटाया है जहां से सहायता मिल सकती है। राम गोपाल जी ने कुछ प्रश्न किए हैं कि खाड़ी के देशों में क्या 70 लाख लोग हैं? हां हैं। क्या उनकी remittances इतनी हैं जितनी टोटल remittances का आधा है? हां है। लेकिन उसके बाद आपने कहा कि हमारी विदेश नीति ऐसी है, जिस विदेश नीति में हम कभी अमेरिका के दबाव में वोट करते है, कभी अमेरिका के पक्ष में वोट करते हैं, कभी हम ऐसे वोट करते हैं, कभी हम अब्सटेन करते है। सवाल तो आप ठीक कर रहे थे मगर निगाह गलत थी। आप मेरी तरफ देखकर सवाल कर रहे थे। यह सवाल आपको उधर करना चाहिए था, बैठे थे प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. राम गोपाल यादव: आप रेक्टिफाइ कर दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं वही कह रही हूं। आप जिस सरकार के समर्थक दल थे ...

प्रो. राम गोपाल यादव: मै तो सरकार को कंटीन्युटी मानता हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज: हां, मैं भी कंटीन्युटी मानती हूं। आपने कहा कि 7 बार हमने वोट किया- कभी एब्स्टेन किया, कभी उनके पक्ष में किया, कभी विरोध में किया। यह प्रश्न आप हमारी तरफ देखकर करने के बजाय उधर की तरफ देखकर करते और उस समय पूछते तो ज्यादा कारगर होता, जब आप उनको समर्थन दे रहे थे। जहां तक हमारा सवाल है, हमारे समय में वोट का प्रश्न केवल यूएनएचआरसी में आया और मैं गर्व से कहती हूं कि यूएनएचआरसी में अपनी परंपरा को कायम रखते हुए भारत ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट किया है, उनके खिलाफ वोट नहीं किया है। इसलिए हम दोषी नहीं हैं। जहां तक इजराइल और गाजा का सवाल है, मैं चाहती थी कि विषय पर चर्चा बहुत फोकस्ड होती, लेकिन वह बिखर गयी और यह बिखरी भी इतनी कि अमेरिका, चाइना, यू.के., इजराइल, गाजा, बर्न—ये सब उसमें आ गए। नरेश भाई तो इसे चाइना तक ले गए, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। अब जो ये सारी बातें हुई, उनके बारे में मुझे सदन को बताने का मौका तो मिला। फिर यह चर्चा इराक से आगे इल्लीगल माइग्रेशन तक चली गयी, रिक्रुट करने वाली एजेसियों तक चली गयी। अम्बिका जी ने पूछा क्या आपके यहां कोई ऐसा ग्रुप है, जो इनके ऊपर नजर रखे ? अम्बिका जी, हमारे यहां केवल ग्रुप नहीं बल्कि पूरी की पूरी मिनिस्ट्री है और आपके समय में मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स बनाई गई, जो केवल यही काम करती है आप एक ग्रुप की बात करते है, वह इंडियन वर्कर्स सिसोर्स सेटर अलग है, माईग्रेंट वर्कर्स रिसोर्स सेटर अलग है और वह पूरा-का-पूरा

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

मंत्रालय यही काम करता है। वायालार रवि जी तो जानते हैं क्योंकि वे उस विभाग के मंत्री रहे हैं। वहां सब से ज्यादा केरल के लोग जाते हैं, तभी उन्होंने कहा कि आप मलयाली के क्यों खिलाफ हैं? अरे भाई, मैं मलयाली के खिलाफ क्यों होऊंगी? हमारा प्रवासी मंत्रालय तो केरलाइट्स पर ही चल रहा है। वहां केरल से इतने ज्यादा लोग जा रहे हैं कि इनके अपने प्रदेश में एक महकमा "नॉर्का" है, जो उनको देखता है। इस तरह पूरा-का-पूरा मंत्रालय यही काम कर रहा है। राजीव जी ने इमिग्रेशन बिल के बारे में पूछा। इनके समय में इमिग्रेशन बिल बना था, लेकिन उस बिल में काफी खमियां हैं। अभी जो 1983 का बिल है, वह बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है। हम उस बिल को रिप्लेस करना चाहते हैं। यह इमिग्रेशन बिल उस समय तैयार हुआ था। हम चाहते हैं कि उसकी कमियों को पूरा कर के एक परफैक्ट बिल लाएं। मुझे लगता है कि हम अगले सत्र तक उस बिल को तैयार कर लेंगे क्योंकि जैसे-जैसे मैं इन सारी चीजों को देखती हूं, वैसे-वैसे दिल दहलता है कि ऐसे-ऐसे एजेंट्स बन गए हैं, जिन्हे यह परवाह बिल्कुल नहीं है कि वे हिंदुस्तानियों से इतनी बड़ी-बड़ी रकम लेकर उन्हें फंसा देते हैं। ऐसे बहुत से केसेज आए हैं, जिनमे लोग एअरपोर्ट पर पहुंचते हैं और एम्प्लॉयर तक पहुंच भी नहीं पाते कि उसके पहले ही जेल चले जाते हैं क्योंकि उसमें सब कुछ फेक होता है, वीजा भी फेक होता है। ऐसी सारी चीजों को इकट्ठा कर के हम लोग इमिग्रेशन के बारे में एक नया बिल बना रहे हैं और उस बिल को हम लोग यहां लेकर आएंगे।

नरेश भाई, आप चुटकी लेते हैं कि प्रधान मंत्री मुझे नेपाल नहीं ले गए, मुझे ब्रिक्स नहीं ले गए। मैं डा. मनमोहन सिंह जी से पूछना चाहूंगी कि आप कब-कब अपने विदेश मंत्री को ब्रिक्स में ले गए? ...(**व्यवधान**)... नरेश जी, आपने झगड़ा कराने की पूरी-की-पूरी कोशिश की कि ब्रिक्स में भी लेकर नहीं गए, नेपाल भी नहीं ले गए। आप झगड़ा मत कराइए। अगर हम यहां से बाहर चले जाते, तो आप कहते प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री-दोनों को जाने की क्या जरूरत थी? जब सत्र चल रहा है, तो एक को तो रहना चाहिए था। आपका मतलब है, "चित भी मेरी पट भी मेरी।" यह नहीं हो सकता है। जब सरकार को कटघरे में खड़ा करना होता है, तब आप नियमों का हवाला देते हैं और जब अपना हित सधता है, तो नियमों को तुड़वाते हैं। मैंने यहां भी सब से कहा कि मैं तैयार हूं, हालांकि नियम इस की इजाजत नहीं दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि मैं दो बजे भी तैयार हूं।

महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि इस विषय पर जो चर्चा हुई, अगर उसे बिखराव से भी छांटूं, तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे निकले, जिनके उत्तर मैं देना चाहती थी और जिनके उत्तर मैंने दिए हैं।

महोदय, एक बात लीबिया में एक केरलाइट डेनियल सोलोमन की डेथ के बारे में कही गई।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: One Soloman Daniel died in Tripoli.

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैं डेनियल सोलोमन के बारे में बताना चाहूंगी। कल यह दुर्घटना हुई। एक बम ब्लास्ट हुआ, उसका स्प्लिंटर उन्हें लगा जिसके कारण उनकी डेथ हुई है। हमारी एम्बैसी ने उसी समय वहां बात कर ली है कि उनके mortal remains, उनका पार्थिव शरीर यहां आ जाए। इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि तुरंत आ जाए, जल्दी आ जाए क्योंकि उसमें कोई अलग से पोस्टमॉर्टम वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। सबको मालूम है कि बम ब्लास्ट में डेथ हुई है। हम जल्दी से जल्दी उनके mortal remains यहां लेकर आएंगे, इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं।

उपसभापति जी, लीबिया में जो लागे फंसे हैं, उनको भी निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं, आपको यह सुनकर गर्व होगा कि लीबिया में जिस तरह का संघर्ष चल रहा है, अमेरिका ने, यू.के. ने, फ्रांस ने, चीन ने अपनी-अपनी एम्बैसियां वहां बंद कर दी हैं। एम्बैसी बंद करने का अर्थ होता है कि लोगों को उनके भाग्य पर छोड़कर चले गए। नरेश जी, आप उधर बात कर रहे थे। लीबिया में अमेरिका ने अपनी एम्बैसी बंद कर दी, फ्रांस ने अपनी एम्बैसी बंद कर दी, ट्यूशीनिया तक ने बंद कर दी, लेकिन भारत की एम्बैसी चौबीसों घंटे काम कर रही है। हमने 70 फील्ड को ऑर्डिनेटर्स लगाए हैं। हमारे एक पुराने अधिकारी, जो पहले लीबिया में एम्बैसेडर रह चुके हैं, मिस्टर कुमारन, उनको हमने स्पेशली भेजा है। वे अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं और हम लोगों ने उसके लिए भी तय किया है कि हम ट्यूशीनिया के रास्ते से भी निकालेंगे। बीच में ट्यूशीनिया का बॉर्डर बंद हो गया था, जो कल से खुल गया है। 98 नर्सें निकल चुकी हैं, 126 नर्सें तैयार हैं जाने के लिए, 236 लोग माल्टा में बेंगाजी से जाने को तैयार हैं, लेकिन जो फेरी, मैंने कहा कि एक लाख रूपए प्रति पर्सन के लिए है, वह 420 की है। तो हम लोग चाहते है कि कम से कम इतने पैसंजर जरूर तैयार हो जाएं कि उनको हम लोग निकाल कर ले जाएं। कल फिर मैंने चांडी जी से बात की है कि आप लीबिया में फोन कीजिए और उनको कहिए कि वे लोग निकल कर आएं। मैं पुनः आप लोगों से कहना चाहती हूं कि इराक और लीबिया में, जो भी आपका कोई परिचित फंसा है, आप उसको यह कहिए कि वह वहां से आ जाए, क्योंकि लीबिया इस समय बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आज के दिन चीज़ें हमारे कंट्रोल में इतनी हैं कि हम निकाल कर ला सकते हैं।

राजीव शुक्ल जी ने एक बैटलशिप की बात थी, तो मैं बता दूं-बैटलशिप यह नहीं कि जा रहा था, चला गया था। आई.एन.एस. मैसूर वहां जाकर खड़ा हो गया था। एयर ट्रैफिक से ही हम लोग निकाल पाए। सारे के सारे विमानों से जब हम ले आए, तो फिर हमें लगा कि उसकी वहां अब आवश्यकता नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 15,000 कुर्दिस्तान में रहने वाले तो निकालने नहीं हैं। ये लोग जो निकल रहे थे, तो वहां आवश्यकता नहीं थी, तो हमने उसको वापस बुला लिया, लेकिन वह बैटलशिप गया था, आई.एन.एस. मैसूर वहां जाकर खाड़ा रहा, बहुत दिनों तक खड़ा रहा। उसको हमने कुवैत से भेजा था, अब वह वापस आ गया है। तो इराक का इवैक्युएशन लगभग पूरा हो गया है। अब तो ट्रिकल डाउन जिसे कहते हैं, कोई एक-एक, दो-दो आ जाता है हमारे पास कभी, तो उसको भी हम लोग निकाल लाते है। आप कोई और सुची देंगे, तो उनको भी निकाल लाएंगे। तो अब हमारा ध्यान ज्यादा लीबिया की तरफ है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि लीबिया में भी हम माल्टा से इधर जरबा के एयरपोर्ट से अपने भारतीयों को निकाल रहे हैं। उनकी सुरक्षा हमारी केवल चिंता ही नहीं, हमारे सबसे बड़ी प्राथमिकता है और मैं आप सबको कहना चाहती हूं कि आप आश्वस्त रहिए, हर भारतीय को, जो वहां असुरक्षित है, हम उसको निकाल कर लाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... No clarifications on clarifications. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA : What about Father Prem Kumar? ...(*Interruptions*)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः जो आपकी दो बातें हैं, मैं बता दूं। एक तो आपने बीमा योजना की बात थी, तो वह भी मैं बता दूं कि 18 ईसीआर कंट्रीज हैं। उनके लिए पहले से प्रवासी भारतीय बीमा योजना चल रही है। आपको मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन ऑलरेडी एक योजना चल रही है-

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

4.00 P.M.

प्रवासी भारतीय बीमा योजना, जिसमें केवल 275 रुपए, अगर आप दो साल के लिए जा रहे हैं और 375 रुपए, अगर आप तीन साल के लिए जा रहे हैं, वन टाइम पेमेंट करनी होती है, जिसमें दस लाख रूपए का बीमा होता है।

जहां तक प्रेम कुमार जी की बात है, इनके फादर को मैंने बुलाया था, उनके पिता को। आप फादर प्रेम कुमार की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बॉयोलॉजिकल पेरेंट्स को मैंने बुलाया था। उनकी मां भी आई थीं, उनकी दोनों बहनें भी आई थीं। अफगानिस्तान के एम्बैसेडर से मैं लगातार सम्पर्क में हूं। हर दिन मुझे पता चलता है किवे जीवित हैं, कुशल हैं, अभी तक हम उनको निकालकर नहीं ला सके हैं, लेकिन उनको भी हम निकाल कर लाएंगे। ...(**व्यवधान**)...

श्री डी.पी. त्रिपाठी: दुबई से इराक जाने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या के बारे में मैंने पूछा था। ...(**व्यवधान**)...

SHRIMATI AMBIKA SONI : Sir, probably, the hon. Minister misunderstood when I said that two statements were identical, with a change in figure. I realize that the change in figure was because, in 10 days, 900 more people had been evacuated. I thought that in ten days there would be some forward movement, as far as 41 captured people are concerned. But there was no re-assurance, even though the hon. Minister had talked on Eid. During the course of my intervention, I gave a lot of important names who are able to get visas in bulk, say, 600 visas at a time, from the Government over there and other authorities. Would she consider sending, in the way she thinks best, one or two people who have the experience of working there, who have worked in this very construction Company, who know the language and who have also the confidence of at least 27 members out of the 41 in India? Would she consider sponsoring these two people to make some headway in Iraq?

श्रीमती सुषमा स्वराज: अम्बिका जी, आप जिनकी बात कर रही हूं और जिनके हवाले से यह बात कह रही है, वे मुझे भी मिल चुके हैं और बहुत बार मिल चुके हैं। वे अभी भी यहीं हैं, लेकिन उनकी जो बात होती है, उस बात को हम वैरीफाई करते हैं। आप गवर्नमेंट में रही हैं, गवर्नमेंट सिस्टम को जानती हैं। जिनकी आप बात कह रही हैं, पहले उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इराक जाने को तैयार हूं। हमने कहा, आप कल चले जाइए, सरकारी खर्चे पर चले जाइए। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि मैं वहां जाने को तैयार नहीं हूं। बाद में जब वे लागे मुझसे मिलने आए तो उन परिवारों के साथ वे आए। मैंने कहा कि पहले आप जाने के लिए तैयार थे लेकिन अब जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी बहन ने कहा कि पहले वाले तो वहां फंसे हुए हैं, अब हम इन्हें वहां क्यों भेज दें, तो ऐसा नहीं है। जिनके हवाले से आप बात कर रही हैं, आपने अबू अब्दुल्ला की बात की, आपने एक दूसरे व्यक्ति की बात की, जिसका आप नाम ले रही हैं, मैं भी जानती हूं कि आप किसके हवाले से कह रही हैं। वे मरे सम्पर्क में हैं और अभी भी यही हैं। जी हां, अभी भी यही हैं, लेकिन केवल उनके कह देने से हम भेज देंगे तो वह नहीं हो सकता है। मुझे इस सिस्टम में काम करना है। हम पूरी तरह से उनकी सहायता

ले रहे हैं। जितनी उनकी सहायता हमें मिल पा रही है, हमें मदद कर पा रही है, वह मदद भी हम लोग ले रहे हैं। आपसे जो व्यक्ति मिला है और जितनी बातें अभी आपने कही हैं, वह जिस व्यक्ति के हवाले से कही हैं, वह डेली मेरे संपर्क में है।

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैंने उनके हवाले से नहीं कही हैं, यह आप गलत इन्सर्ट कर रही हैं। ...(**व्यवधान**)...

STATEMENT BY MINISTER

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now statement by hon. Minister, Dr. Jitendra Singh on Civil Services Examination conducted by the UPSC.

On the issue of Civil Services Examination conducted by UPSC

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डा. जितेंद्र सिंह): सभापति महोदय, सिविल सेवा परीक्षा के विवाद को लेकर काफी समय से चिंता बनी हुई है। इस सभा में यह विषय बार-बार उठता रहा है। सरकार ने बड़ी गंभीरता और बड़े धीरज के साथ इस विषय का अध्ययन किया है, सभी भिन्न भिन्न पक्षों को सुनने का प्रयास भी किया है। विद्यार्थियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सरकार का यह मत है कि सिविल सेवा प्रारम्भिक परीक्षा प्रश्न पत्र-2 में अग्रेंज़ी भाषा वाले प्रश्न-भाग के अंकों को ग्रेडेशन अथवा मैरिट के लिए सम्मिलित करने का कोई औचित्य नहीं है। The Government is of the opinion that in the Civil Services Preliminary Examination, Paper-II, the marks of the question section on "English Language comprehension skills" should not be included for gradation or merit. सरकार का यह भी मत है कि सिविल सेवा परीक्षा 2011 के उम्मीदवारों को एक और अवसर 2015 में दिया जाना चाहिए। The Government is also of the opinion ...(*Interruptions*)..

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Sir, I am not arguing about the English but the students who appear from the Southern part of India may not know Hindi as well. They should be protected. ...(*Interruptions*)... What is this? ...(*Interruptions*)... They have to be protected. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, it cannot be like that. ...(*Interruptions*)... It should be discussed. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): All languages are national languages. Malayalam, Telugu, Tamil, all these are national languages. ...(*Interruptions*)...

SHRI D. RAJA: Sir, there should be a level-playing field. ...(*Interruptions*)...

SHRI P. RAJEEVE: This is a very serious issue, Sir. ...(*Interruptions*)...